04 - सुरेश गोपी यानि केरल में खिला कमल

05 - हार का मंथन व जीत की विवेचना आवश्यक

A Daily News Magazine
भोपाल
शनिवार, 29 जून, 2024

06- विधायकों ने कहा बैतूल का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

07- पूजन-हवन के साथ सत्यनारायण भगवान प्रतिमा का पुर्नस्थापना...

सुबह सवेरे

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 21 अंक 292 नगर संस्करण, पृष्ठ -8, मूल्य रू.- 2 (डाक पंजीयन संख्या: म.प्र./भोपाल/4-391/2018-20)

प्रसंगवश

बीजेपी में अब फिर दिखने लगे हैं लोकतंत्र के संकेत

डीके सिंह

बीते दशक में भारतीय जनता पार्टी में सत्ता के बढ़ते केंद्रीकरण और हाई कमान के नियंत्रण पर बहस होती रही है। कई लोगों ने इसे भाजपा के कांग्रेसीकरण का नाम दिया है। मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और पार्टी के पदाधिकारियों को लगभग मन-मुताबिक हटाया और बनाया जाता है। परामर्श का सवाल ही नहीं उठता। चतुर भाजपा नेताओं को जल्द ही सफलता का भेद पता चल गया- झुका हुआ सिर, नीची आंखें, जुड़े हुए हाथ, झुकी हुई रीढ़ की हड्डी व सिले होंठ जिसे तभी खोलना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सराहना करनी हो।

4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद, सत्तारूढ़ पार्टी में बदलाव की हवा चलनी शुरू हो गई है। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में शामिल होने के बाद नई दिल्ली से भोपाल तक की ट्रेन यात्रा को ही लें। भाजपा कार्यकर्ताओं की बड़ी, उत्साही भीड़, रेलवे स्टेशनों पर उनका स्वागत करने वाले लोग और भोपाल में रोड शो, ये सब बता रहे थे कि चौहान क्या कहना चाहते हैं। शिवराज चौहान, जिन्हें गलत तरीके से सीएम पद से वंचित किया गया था, को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर नहीं रखा जा सकता था। पीएम ने उन्हें कृषि और ग्रामीण विकास विभाग आवंटित किए। लेकिन यह भी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए एक उपलब्धि थी। यही इस बात की अभिस्वीकृति थी कि उन्होंने मध्य प्रदेश में कृषि को किस तरह बदला है।

जब से मोदी-शाह केंद्र में आए हैं, तब से कोई भी अन्य पार्टी नेता अपनी ताकत दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाया। चौहान से लेकर वसुंधरा राजे, रमन सिंह, देवेंद्र फडणवीस और बीएस येदियुरप्पा जैसे लोगों की ऐसी लोकप्रियता उनका कमजोर प्वाइंट हो गया। इसी पृष्ठभूमि में चौहान की ट्रेन से बदलाव की सीटी सुनाई दी। चौहान के बेटे कार्तिकेय की यह टिप्पणी कि पूरी दिल्ली उनके पिता के सामने 'नतमस्तक या झुकती' है, शायद एक बेटे के गर्व की भावना को दर्शाता है। हालांकि, इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई ज़रूर है जिससे सत्ता के गलियारे में हर कोई चौहान के हर एक कदम पर नज़र रख रहा है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से जुड़ा है, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पेपर लीक मामले को लेकर मोदी सरकार की बढ़ती आलोचना के बीच, बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता विजय सिन्हा ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव को इससे जोड़ने की कोशिश की। सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि तेजस्वी के निजी सचिव ने एनएचएआई के गेस्ट हाउस में पेपर लीक के आरोपी के लिए एक कमरा बुक किया था। भाजपा नेता के आरोप के जोर पकड़ने से पहले ही एनएचएआई ने तुरंत एक बयान जारी कर दिया- 'एनएचएआई यह स्पष्ट करना चाहता है कि एनएचएआई के पास पटना में कोई गेस्ट हाउस की सुविधा नहीं है।' इसने बिहार के उपमुख्यमंत्री के दावों की धार को कुंद कर दिया।

गडकरी की बात करें तो, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की बैठक में जहां मोदी को इसका नेता चुना गया था, मंच पर पीएम और पार्टी के गठबंधन सहयोगियों के साथ तीन बीजेपी नेता बैठे थे- अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गडकरी को सांसदों और अन्य मंत्रियों के साथ नीचे बैठाया गया था। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर नड्डा का वहां होना जरूरी था। लेकिन शाह और सिंह का क्या? अगर वे पूर्व बीजेपी अध्यक्षों के तौर पर मंच पर थे, तो नितिन गडकरी को वहां बैठने के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना चाहते थे। बीजेपी आलाकमान चाहता था कि गडकरी महाराष्ट्र चले जाएं जहां पार्टी नाजुक स्थिति में है। हालांकि, कहा जाता है कि संघ ने इस पर अड़ंगा लगाया और सुनिश्चित किया कि गडकरी को उसी पोर्टफोलियो के साथ कैबिनेट में शामिल किया जाए। महाराष्ट्र में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा देने की अपनी मंशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि वह केंद्रीय नेतृत्व से अनुरोध करने जा रहे हैं कि उन्हें सरकार में उनकी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए ताकि वह अपना पूरा समय भाजपा को मजबूत करने में लगा सकें। अब ये ऐसे फैसले नहीं हैं जिसके बारे में माना जाता है कि भाजपा नेता खुद लें। कोई यह तर्क दे सकता है कि फडणवीस हमेशा से ऐसे ही थे। उन्होंने पहले भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने की अपनी अनिच्छा सार्वजनिक रूप से जाहिर की थी।

देखें कि राज्यों में क्या हो रहा है। असम में अमित शाह के विश्वासपात्र मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को अपनी पार्टी के भीतर ही असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। यह कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की जोरहाट से जीत का नतीजा है, जिसे सीएम और उनकी टीम ने अपने प्रतिष्ठा की लड़ाई बना रखी थी। एक अन्य भाजपा विधायक और पूर्व राज्य भाजपा प्रमुख सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने भी गोगोई की सराहना की और उनकी जीत को उनका 'राजनीतिक राज्याभिषेक' कहा। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा ने चुप रहना ही बेहतर समझा। पश्चिम बंगाल के पूर्व भाजपा प्रमुख दिलीप घोष पार्टी नेतृत्व के इस फैसले पर मुखर रूप से सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें और अन्य नेताओं को जीतने वाले निर्वाचन क्षेत्रों से हटाकर चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भेजा गया, जिससे उनकी हार हुई।

लोकसभा चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की हार के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके और पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच ठन गई है। आलाकमान उनकी लड़ाई को असहाय होकर देख रहा है। बदलाव के संकेत हर जगह दिख रहे हैं। आलाकमान भले ही ताकतवर बना हुआ हो, लेकिन अब उसे लेकर वह डर और खौफ नहीं है जैसा कुछ हफ्ते पहले तक हुआ करता था। मोदी-शाह शासन के दौरान दरकिनार किए गए लोग अपनी जगह बनाने में लगे हैं और अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं। पार्टी अपनी पुरानी ताकत को फिर से तलाशने लगी है - यानी आंतरिक लोकतंत्र, जिसने मोदी और शाह जैसे नेताओं को उभरने में मदद की।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

नीट मामले पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा

कांग्रेस अध्यक्ष वेल में पहुंचे, सभापति धनखड़ बोले-यह संसदीय इतिहास पर काला धब्बा

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद सत्र के पांचवें दिन शुक्रवार को नीट मुद्दे के चलते दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में कार्यवाही हंगामे के चलते 1 जुलाई तक स्थगित कर दी गई। हालांकि राज्यसभा में कार्यवाही रुक-रुककर चलती रही। बाद में इसे भी 1 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया। दरअसल, विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया था। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के बीच स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाता। जबकि राज्य सभा में 22 सांसदों के नोटिस को सभापति ने खारिज कर दिया। 24 जून से शुरू हुआ संसद का यह सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। राज्य सभा में पीएम मोदी 3 जुलाई को चर्चा का जवाब दे सकते हैं। नीट मामले पर चर्चा की मांग के दौरान राज्यसभा में चेयरमैन जगदीप धनखड़ और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच विवाद की स्थिति बनी। हंगामे के बीच खड़गे सभापति की आसंदी के पास पहुंच गए, जिस पर धनखड़ भड़क गए और कार्यवाही 2 बजे तक रोक दी। खड़गे सदन से बाहर आकर बोले कि यह चेयरमैन की गलती है। मैं उनका ध्यान खींचने के लिए अंदर गया था लेकिन, तब भी वे नहीं देख रहे थे। वे केवल सत्ता पक्ष को देख रहे थे। नियमानुसार उन्हें मेरी तरफ देखना चाहिए, लेकिन उन्होंने जानबूझकर मुझे अनदेखा करके मेरा अपमान किया। तो मेरे लिए क्या बचा था। मुझे या तो अंदर जाना होगा या बहुत जोर से चिल्लाना होगा। प्रदर्शन कर रहीं कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम को चक्कर आ गया।

बिहार विधानसभा और विधान परिषद का न्यू डेटा

लोकसभा रिजल्ट के बाद 'बड़े भाई' के रोल में फिर बीजेपी

पटना (एजेंसी)। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में फिलहाल भाजपा के सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है। विधानसभा में भाजपा के अब 78 विधायक हैं, जबकि विधान परिषद में उनकी सदस्यों की संख्या 24 है। विधानसभा अध्यक्ष पद हो या विधान परिषद सभापति, दोनों पर भाजपा काबिज है। विधानसभा में नंदकिशोर यादव अध्यक्ष हैं तो विधान परिषद में अवधेश नारायण सिंह कार्यकारी सभापति हैं। कहा जा रहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा अभी से ही रणनीति बनाने में जुट गई है। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर के लोकसभा जाने के बाद भाजपा के अवधेश नारायण सिंह कार्यकारी सभापति चुने गए। माना जा रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव और हाल में ही हुए लोकसभा चुनाव में शाहाबाद और मगध की हार के बाद विधान परिषद में राजपूत समुदाय के अवधेश नारायण सिंह को सभापति बनाकर पार्टी के रणनीतिकारों ने सवर्णों को एक संदेश देने की कोशिश की है।

मुख्यमंत्री ने की कृषि हितग्राही मूलक योजनाओं की समीक्षा

कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था के प्रति किसानों का विश्वास बरकरार रहे : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में तुअर के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए। कोदो-कुटकी के रकबे को बढ़ाने से पानी-बिजली का उपयोग संतुलित होगा तथा फसल चक्र में भी सुधार होगा। अतः किसानों को कोदो-कुटकी की फसल लेने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। फसल चक्र पर ग्रीष्मकालीन फसल लेने के नकारात्मक प्रभाव से भी कृषकों को अवगत कराना जरूरी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कृषक हितग्राही मूलक योजनाओं सहित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा कृषि विविधीकरण के लिए किया जा रहे प्रयासों पर मंत्रालय में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री ऐदल सिंह कंषाना, मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा उपस्थित थीं।

कृषि उपज मंडी में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित सचिव होंगे जिम्मेदार- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारी मंडियों के तौल-काँटे, वित्तीय लेन-देन तथा अन्य व्यवस्था का आकस्मिक निरीक्षण करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों के हितों से कहीं भी खिलवाड़ ना हो और मंडी व्यवस्था के प्रति किसानों का विश्वास बरकरार रहे। कलेक्टर कृषि उपज मंडी के संचालन पर भी निगरानी रखें। कहीं पर भी कृषि उपज मंडी में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित सचिव जिम्मेदार होंगे, उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वेयरहाउस निर्माण व उपयोग के प्रावधानों में किसानों के हितों को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सीमांत, लघु कृषकों को लाभ मिले- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश, जलवायु परिस्थितियों, मिट्टी और फसलों के विविध पैटर्न के साथ संपन्न है। हमारे किसान भाईयों की अथक मेहनत से प्रदेश कृषि विकास में सर्वोपरि है। हमारा प्रदेश दलहन व तिलहन के क्षेत्र तथा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। किसानों की आय में वृद्धि करने तथा कृषि को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में हम निरंतर प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अधिक से अधिक सीमांत, लघु कृषकों को लाभ मिले यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाएं। रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पौष्टिक श्रीअन्न का उत्पादन बढ़ाने और इसकी पैदावार करने वाले कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं।

फसल विविधीकरण को करें प्रोत्साहित- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि धान एवं गेहूँ के स्थान अन्य लाभकारी फसलें लेने के लिए फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाए। ऐसी फसलों को बढ़ावा दिया जाए जो सरकारी खरीद पर निर्भर नहीं हों और जिनका दाम बाजार व निर्यात की मांग से जुड़ा हो। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता बताते हुए प्रदेश के सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को विस्तारित करने संबंधित कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 25 लाख से अधिक किसान हुए लाभान्वित

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्ष 2023-24 में 25 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। बीमा दावों का भुगतान भी त्वरित रूप से किया जा रहा है। अटल कृषि ज्योति योजना में 25 लाख 61 हजार, निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना में 9 लाख 21 हजार और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 80 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में राज्य मिलेट मिशन में वर्ष 2024-25 में कोदो-कुटकी, रागी और ज्वार के 1166 क्विंटल प्रमाणित बीजों का वितरण किया गया। किसानों को कोदो-कुटकी पर एक हजार रुपये प्रति क्विंटल की दर से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

शाम से ही कुछ उदासी लग रही है,
ये घटाएं आज प्यासी लग रही है।

किस कदर बाज़ार में उलझे रहे तुम,
घर की रोटी आज बासी लग रही है।

जो असल मालिक है अपने ही वतन की,
वो ही जनता आज दासी लग रही है।

झूठ के हैं, हाथ में फंदे हजारों
और सच को फिर ये फांसी लग रही है।

हिचकियाँ आती थी उनकी याद में ही,
अब तो बस थोड़ी सी खांसी लग रही है।

बद नज़र से उसको कोई छू गया था,
आज वो बच्ची रुआंसी लग रही है।

बात गुंजन की सही निकली है देखो,
बू खिताबों में सियासी लग रही है।

– गोविंद गुंजन

सांसद फूलो देवी की बिगड़ी तबियत

● नीट पेपर लीक मुद्दे पर संसद में कर रहीं थी विरोध-प्रदर्शन

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सदस्य और छत्तीसगढ़ की वरिष्ठ नेता फूलो देवी नेताम शुक्रवार को संसद में विरोध प्रदर्शन के दौरान बेहोश हो गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वह नीट मुद्दे पर सदन के वेल में विरोध कर रही थीं, तभी उन्हें चक्कर आने लगे। उन्हें दिल्ली के आरएमएल अस्पताल ले जाया गया है। इसका वीडियो भी सामने आया है। एबुलेंस में आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी बैठी हुई नजर आ रही हैं। संसद के पांचवें दिन की शुरुआत से ही संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष आक्रामक नजर आया।

वैन और लॉरी की टक्कर के बाद मचा कोहराम, 4 लोग घायल

कर्नाटक में भीषण सड़क हादसा, 13 की मौत

गाड़ी में 17 लोग सवार थे, ड्राइवर को झपकी आने से हुआ हादसा

हावेरी (एजेंसी)। कर्नाटक के हावेरी जिले में वैन और लॉरी की टक्कर में दो बच्चों सहित 13 लोगों की मौत हो गई। चार घायल हैं। वैन में 17 लोग सवार थे। पुलिस ने बताया, हादसा सुबह 3.45 पर हुआ। जब वैन हावेरी जिले के बयादागी में हाईवे किनारे खड़ी एक लॉरी से टकरा गई। चार घायलों में से दो आईसीयू में एडमिट हैं। हावेरी एसपी अंशु कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक, वैन में सवार सभी लोग चिंचोली मयम्मा देवस्थान से आ रहे थे और शिवमोग्गा लौट रहे थे। तभी वैन ने लॉरी को पीछे से टक्कर मार दी। शुरुआती जांच में सामने आया कि ड्राइवर को झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने कहा कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि, कुछ शव वैन के टूटे हिस्सों में फंस गए थे। फायर ब्रिगेड की मदद से उन्हें निकाला गया। मृतकों की पहचान नागेश, विशालाक्षी, आदर्श, अर्पिता, परशुराम, भाग्य, पुण्य, मनसा, रूपा, सुभद्रा बाई, मंजुला बाई और मंजुला के रूप में की गई है। एक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर दुख जताते हुए लिखा-कर्नाटक के हावेरी जिले में एक बस दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित कई तीर्थयात्रियों की मौत की खबर दुखद है।

पानी-पानी हुई दिल्ली, टूटा 88 साल का रिकॉर्ड

सड़कें जलमग्न, कई जगहों पर टूटे पेड़ और डूबीं गाड़ियां

नई दिल्ली (एजेंसी)। चिलचिलाती गर्मी और गर्म हवाओं के मौसम के बाद जब बारिश ने सर्द लहजे के साथ दस्तक दी तो हर किसी के चेहरा खिल उठा। लेकिन शुक्रवार की सुबह से बरस रहे बादल राजधानी दिल्ली की व्यवस्थाओं के लिए हर बार की तरह आफत बनते दिख रहे हैं। शहर की सड़कों पर बहता पानी और रुकी हुई गाड़ियों ने सरकारी इंतिज़ाम की पोल खोल कर रख दी है। इतनी बारिश कि रिकॉर्ड तक कायम हो गया। जानकारी ऐसी है कि 88 साल बाद जून के महीने ने इतनी बारिश देखी है। जब सुबह बारिश शुरू हुई तो खबर आई कि आईजीआई एयरपोर्ट पर छत का एक हिस्सा गिर गया। जिससे एक शख्स की मौत भी हो गई। आम लोगों को हो रही ऐसी दिक्कतों से जुड़ी खबरें कई और जगह से भी सामने आ रही हैं। दिल्ली में कई जगह लंबा ट्रैफिक जाम है। भारतीय मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार सुबह 8.30 बजे तक पिछले 24 घंटों में सफदरजंग बेस स्टेशन पर 228.1 मिमी बारिश दर्ज की गई है। सुबह 2.30 बजे से 5.30 बजे तक सफदरजंग स्टेशन पर 148.5 मिमी बारिश दर्ज की गई है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 40.5 °c | न्यूनतम 36°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शनिवार, 29 जून 2024

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

दुर्योधन का मंदिर, सरकार लेती है टैक्स

ताड़ी का लगता है भोग, 'अपूपा' (दादा) कहते हैं ग्रामीण

तिरुअनंतपुरम (एजेंसी)। केरल को मंदिरों की भूमि माना जाता है। यहां कई प्राचीन मंदिर हैं। कोल्लम जिले के एक सुदूर गांव में दुर्योधन का एक मंदिर है जो अपने आप में खास है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, यह मंदिर कर चुकाता है। किवदंती है कि राजकुमार दुर्योधन अपनी यात्रा के दौरान थक गए और उन्हें प्यासे लगी। वह पीने के लिए पानी को भटक रहे थे। उन्हें तथाकथित निम्न जाति की महिला ने पीने के लिए ताड़ी दी। दुर्योधन ने इसे खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया। उन्होंने महिला और गांव को आशीर्वाद दिया और उन्हें जमीन दे दी। यहीं पर उनका एक मंदिर भी है। पेरुविरुथी मलानाडा मंदिर में दुर्योधन को प्रतिदिन ताड़ी चढ़ाई जाती है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। यहां बस एक पॉलिश की हुई गदा रखा गया है। आपको बता दें कि महाभारत में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश देते समय दुर्योधन खुशी से चिल्लाता है। ग्रामीण उसे 'अपूपा' (दादा) कहते हैं। ग्रामीणों का ताड़ी चढ़ाने के बारे में दिलचस्प दृष्टिकोण है।

गरीब परिवार को साल में 3 मुफ्त सिलेंडर, किसानों को 5000 प्रति हेक्टेयर बोनस

महाराष्ट्र में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 कैश

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने गुरुवार को राज्य का बजट पेश किया। इसमें महिलाओं और किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। किसानों के बिजली बिल बकाया माफ करने से लेकर उन्हें खेती के लिए बोनस देने और महिलाओं को हर महीने रुपए ट्रांसफर करने की योजना शामिल हैं। राज्य में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। फिलहाल राज्य में बीजेपी-शिवसेना (शिंदे गुट) और एनसीपी की सरकार है। इसका कार्यकाल 8 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। ऐसे में अक्टूबर 2024 में चुनाव होने की संभावना है। उससे तीन महीने पहले राज्य सरकार इन योजनाओं को लेकर आई है। राज्य के सभी किसानों को कपास और सोयाबीन की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 5000 रुपए का बोनस दिया जाएगा। दुग्ध किसानों को 1 जुलाई 2024 के बाद भी पांच रुपए प्रति लीटर बोनस दिया जाएगा। किसानों के परिजन को 20 की जगह 25 लाख मिलेंगे।

संक्षिप्त समाचार

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाहर होंगे बाइडेन !

- डिबेट देख घबराई डेमोक्रेटिक पार्टी, ट्रंप ने जमकर लगाई क्लास

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों के बीच डिबेट हुई। इस डिबेट में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन कई बार फंसते हुए दिखे। वहीं ट्रंप का आक्रामक रूप देखने को मिला। ट्रंप लगातार बाइडेन की नीतियों, माइग्रेशन क्राइसिस, रूस यूक्रेन युद्ध को न संभाल पाने का मुद्दा उठाते रहे। इस डिबेट के दौरान बाइडेन फ्रीज होते रहे

और घबराते दिखे। उन्होंने कई गलत बयान दिए, जिससे उनकी डेमोक्रेट पार्टी में नाराजगी और चिंता पैदा हो गई है। चुनाव में अब चार महीने से भी कम का समय बचा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन्हें उम्मीदवारी से हटाया जा सकता है। इस डिबेट के बाद मुख्य राष्ट्रीय संवाददाता जॉन किंग ने बताया कि आखिर बाइडेन की पार्टी के लोग क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बाइडेन से खुद पद छोड़ने के लिए कहना चाहते हैं। वहीं कुछ लोग सार्वजनिक रूप से इस बारे में बोलने की सोच रहे हैं।

एमएलए बेदी राम अंडरग्राउंड, ओपी राजभर दिल्ली पहुंचे

- पेपर लीक स्टिंग पर योगी सख्त, सीबीआई ने जांच शुरू की

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी में पेपर लीक स्टिंग में नाम आने के बाद सुभासपा विधायक बेदी राम अंडरग्राउंड हो गए हैं। वह दो दिन से कहां हैं, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिल रही है। पार्टी के नेताओं को भी उनकी लोकेशन की जानकारी नहीं है। मोबाइल बंद है। पेपर लीक स्टिंग पर सरकार भी सख्त है। गुरुवार को सीएम योगी ने सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर को तलब किया। मुलाकात के बाद शुक्रवार सुबह

राजभर दिल्ली पहुंच गए हैं। भाजपा हाईकमान ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। दरअसल, बेदी राम का 26 जून को एक वीडियो सामने आया। इसमें वह एक युवक से पेपर और लेन-देन की बात कर रहे हैं। बेदी राम कह रहे हैं- मैं बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश कई राज्यों में भर्ती कराता हूं। एक-एक परीक्षा में 40-40 लोगों की भर्ती कराता हूं। इधर, सरकार ने स्टिंग वीडियो की जांच में सीबीआई को लगा दिया।

केन्द्र सरकार ने शुरू की जनता को खुश करने की बड़ी तैयारी

अधिकारियों संग जल्द बैठक कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी

आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर फोकस

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह ही अपने आला अफसरों के साथ बड़ी बैठक करके जनहित के कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले ही पीएम मोदी ने अधिकारियों को पहले 100 दिन का एजेंडा तैयार करने का काम सौंप दिया था। अब बारी है सरकार को काम करके दिखाने की। अधिकारियों के साथ बैठक में जनहित की योजनाओं और आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने को लेकर चर्चा हो सकती है। वहीं सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी विभागवार भी 125 दिनों के एजेंडे की समीक्षा कर सकते हैं। इसमें अंत्योदय के सिद्धांत पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा सकता है। मामले से जुड़े एक शख्स ने बताया,

अधिकारियों के साथ बैठक में पांच साल के रोडमैप पर भी चर्चा हो सकती है कि इस कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या कदम उठाने होंगे।

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाहर होंगे बाइडेन!

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों के बीच डिबेट हुई। इस डिबेट में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन कई बार फंसते हुए दिखे। वहीं

ट्रंप का आक्रामक रूप देखने को मिला। ट्रंप लगातार बाइडेन की नीतियों, माइग्रेशन क्राइसिस, रूस यूक्रेन युद्ध को न संभाल पाने का मुद्दा उठाते रहे। इस डिबेट के दौरान बाइडेन फ्रीज होते रहे और घबराते दिखे। उन्होंने कई गलत बयान दिए, जिससे उनकी डेमोक्रेट पार्टी में नाराजगी और चिंता है।

एनडीए के घटक सांसदों से मिले प्रधानमंत्री मोदी

- चिराग से बोले-आपने खुद को साबित किया है

नई दिल्ली (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चिराग पासवान की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि उन्होंने खुद को योग्य साबित किया है और अपने पिता के सपनों को पूरा कर रहे हैं। चिराग पासवान लोजपा (रामविलास) के अध्यक्ष हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे हैं। समाजवादी नेता रामविलास पासवान ने लोजपा का गठन किया था और उनके निधन के बाद पार्टी दो धड़ों में विभाजित हो गई थी। एक धड़े का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री व रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं, जबकि दूसरे धड़े का नेतृत्व चिराग पासवान के हाथों में है। दोनों ही धड़े राजग के सदस्य हैं। लोकसभा चुनाव के लिए समझौते के तहत भाजपा ने लोजपा (रामविलास) को पांच सीट दी थी।

उज्जैन में बारिश, मंदिर में भरा पानी

भोपाल-इंदौर में बादल छाए; पूरे म.प्र.में एक्टिव हुआ मानसून

भोपाल (नप्र)। मानसून ने पूरे मध्यप्रदेश को कवर कर लिया है। आज दक्षिण-पश्चिम मानसून प्रदेश के मऊगंज, सीधी और सिंगरौली के उत्तरी हिस्सों में भी पहुंच गया था। मौसम विभाग ने शुक्रवार को इन हिस्सों में मानसून के पहुंचने की घोषणा कर दी थी। इससे पहले ये ग्वालियर, भिंड, मुरैना समेत 6 जिलों में पहुंचा।

आज सुबह उज्जैन में बारिश हुई। चामुंडा माता मंदिर में बारिश का पानी भर गया। भोपाल और इंदौर में बादल छाए हैं। वहीं, गुरुवार को भोपाल, ग्वालियर, धार, उज्जैन समेत 15 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। तापमान में भी गिरावट आई है। धार में दिन-रात के टेम्प्रेचर में सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर रहा।

सिवनी-डिंडोरी में तेज बारिश का अलर्ट- मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में प्रदेश के सिवनी और डिंडोरी में तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया है।सीहोर, देवास, शाजापुर, मंडला, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, बालाघाट, अनूपपुर के अमरकंटक, आगर-मालवा, उज्जैन, नीमच में भी आकाशीय बिजली चमकने के साथ तेज बारिश होने की संभावना है।

एडीजी उपेंद्र कुमार जैन बने स्पेशल डीजी

राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह का कार्यकाल बढ़ा

भोपाल (नप्र)। राज्य शासन ने शुक्रवार को एडीजी उपेंद्र कुमार जैन को विशेष पुलिस महानिदेशक बनाया है। इससे पहले वे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वहीं, उनके पास मप्र पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम के प्रबंध संचालक की भी जिम्मेदारी थी, जो यथावत रहेगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह का कार्यकाल बढ़ा- मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह का कार्यकाल बढ़ा दिया है।

जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट में वर्षा के कारण एक करोड़ से बनी कैनोपी फटी

जांच के लिए मुंबई से पहुंचेगी टीम

जबलपुर (नप्र)। डुमना एयरपोर्ट टर्मिनल के बाहर लगी कैनोपी (एक तरह की कपड़े की कृत्रिम छत) गुरुवार की सुबह फट गई थी। भरा पानी तेज रफ्तार से नीचे खड़ी कार की छत पर गिरा था। कार में सवार चालक को मामूली चोट आई लेकिन हादसे की भयावक तस्वीर देखकर चालक भी सदमे में आ गया।

कार मालिक को नुकसान की भरपाई करने का भरोसा दिया-एयरपोर्ट प्रबंधन ने कार मालिक को नुकसान की भरपाई करने का भरोसा दिया जिसके बाद मामले की रिपोर्ट नहीं की गई लेकिन घटना की वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित होने के बाद प्रबंधन ने इसके लिए सार्वजनिक माफी मांगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअली लोकार्पण किया था-10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री ने नरेन्द्र मोदी के हाथों वर्चुअली डुमना एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ था। करीब 450 करोड़ रुपये की लागत से इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण का कार्य हुआ है। टर्मिनल भवन बनाने में करीब 100 करोड़ रुपये का खर्च आया है। इस भवन के बाहर लगी कैनोपी के लिए एक करोड़ रुपये की राशि दिल्ली की केजीएन कंपनी के द्वारा करवाया गया था।

क्या था मामला-कार एमपी 20 जेड सी 5496 आयकर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर बालामूर्ति कृष्णा के पास अटैच है। गुरुवार सुबह ज्वाइंट कमिश्नर इंदौर से जबलपुर आ रहे थे। उन्हें लेने कार चालक अभिषेक एयरपोर्ट पहुंचा। उसने कार को प्रवेश द्वार के पोर्च पर खड़ा किया। वह कार के अंदर बैठा था।

पानी वेग के साथ कार के ऊपर गिरा-तभी लगभग पौने आठ बजे केनओपी फटा और उसमें भरा पूरा का पूरा पानी वेग के साथ कार के ऊपर जा गिरा। वेग इतना था कि कार का छत जहां पूरी तरह से चरपट हो गया, वहीं आगे और पीछे के कांच समेत दरवाजे के कांच टूट गए। घटना से अभिषेक दहशत में आ गया और कार से उतरकर भागा।

पांच साल का रखरखाव-केजीएन कंपनी के पास कैनोपी लगाने के बाद इसके रखरखाव का जिम्मा है। निर्माण के बाद पांच साल तक कैनोपी में होने वाली समस्या के लिए कंपनी प्रबंधन की तरफ से काम करना होगा।

एयरपोर्ट प्रबंधन ने कैनोपी बनाने वाली कंपनी से ड्राइन डिजाइन से लेकर तकनीकी पहलुओं को लेकर जांच करने के लिए बुलाया है। इसके लिए विशेषज्ञों का दल बुलाया गया है जो यह जांच करेगा कि आखिर किस वजह से पानी की निकास पर्याप्त नहीं हुई और यह हादसा हुआ।

कैनोपी की छत फटने की जांच के लिए विशेषज्ञों को बुलाया गया है। निर्माण कंपनी डिजाइन और तकनीकी पहलुओं को समझकर उसमें सुधार करेंगे। विभागीय स्तर पर भी इसकी जांच हो रही है।

आरआर पांडे, डायरेक्टर एयरपोर्ट

हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत

करीब पांच महीने बाद जेल से बाहर आए झारखंड के पूर्व सीएम

रांची (एजेंसी)। झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। भूमि घोटाले मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी की ओर से गिरफ्तार किया गया था। अदालत के फैसले के बाद वह जेल से बाहर आ गए हैं। हेमंत सोरेन को राहत मिलने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस के नेताओं-कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद झारखंड की राजनीति में कई बदलाव भी देखन को मिल सकता है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने हेमंत सोरेन को नियमित जमानत दे दी। इससे पहले 13 जून को हेमंत सोरेन के अधिवक्ता और ईडी के एएसजी एसपी राजू की दलील पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। रांची के बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन की हेराफेरी मामले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। ईडी की ओर से हिरासत में लिए जाने के बाद हेमंत सोरेन की ओर से अपने पद से त्यागपत्र दे दिया गया था और उसके बाद से हेमंत सोरेन रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में हैं। अब अदालत का फैसला आने के बाद उनकी जेल से रिहाई को लेकर प्रक्रिया पूरी की गई।

दरिया का सारा नशा ही उतरता चला गया...

- नेहरू का जिक्र कर सुधांशु ने कांग्रेस को खूब सुनाया

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद में सुधांशु त्रिवेदी ने चुनाव नतीजों का जिक्र करते हुए विपक्ष को जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तीन चुनाव के बाद भी तीन अंकों में नहीं पहुंच पाई। फिर भी इतनी खुश है। इसके पीछे वह मानसिकता है, जिसमें फेल होने वाला बच्चा यदि थर्ड डिविजन

से भी पास हो जाए तो बहुत खुश होता है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा,तीसरी बार में भी तीन डिजिट में न आ पाने वाले लोग आखिर क्यों पटाखे दाग रहे थे। उन्होंने विपक्ष के फिर चूक जाने को लेकर गजल की कुछ लाइनें भी पढ़ीं। कहा-दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वह डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। मंजिल समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग,मैं ऐसे रास्तों से गुज़रता चला गया।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बदलेंगे रिवाज

राज्यों के कृषि मंत्रियों को बुलाया,मोदी सरकार में पहली बार

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के नए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य के कृषि मंत्रियों से मुलाकात करने जा रहे हैं। खबर है कि बैठकों का दौर 1 जुलाई से शुरू हो सकता है। हालांकि, इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। खास बात है कि एनडीए सरकार के बीते दो कार्यकालों में पहली बार राज्य के मंत्रियों के साथ ऐसी परामर्श बैठकें नहीं हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, चौहान सबसे पहले छत्तीसगढ़ और असम के मंत्रियों के साथ बैठकें करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा पता चला है कि कृषि मंत्रालय ने राज्य के मंत्रियों को पत्र लिखकर बातचीत के लिए बुलाया है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि साथ ही उन्हें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने और संबंधित राज्यों में किसानों और खेती की स्थिति पर अपने विचार रखने के लिए कहा गया है। बातचीत में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने कहा कि वह राज्य सरकार की तरफ से लागू की गईं

केंद्र की योजनाओं के तहत यूनिट कॉस्ट में संशोधन की मांग को रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार बाजरा की खेती के प्रचार और उत्पादन के लिए कोल्ड चेन स्टोरेज जैसे मुद्दों पर समर्थन मांगेगी।

मंत्री बोले-पत्नियां पति से कहें कि शराब घर लाकर पिएं

भोपाल में महिलाओं से कहा- घर में उन्हें बेलन दिखाएं, खाना न दें

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार में मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने अजीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं बाहर शराब पीने वाले अपने पतियों से कहें कि वे शराब घर लाकर पिएं।

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह भोपाल में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने महिलाओं से कहा- माताएं-बहनें चाहें कि मेरा पति दारू न पिए, पहले तो उसे बताएं कि आप बाजार में मत पिओ, आप तो ले आओ, मेरे सामने पिओ। सामने पिएंगे तो उनकी लिमिट कम होती जाएगी। धीरे-धीरे वो बंद की कगार पर आ जाएगी। उसे शर्म आएगी कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के सामने शराब पी रहा हूं। उसे वो भी बातें बताएं कि तुम्हारे बच्चे आगे शराब पिएंगे। शराब उसकी बंद हो जाएगी, ये बिल्कुल प्रेक्टिकल है। वो शराब छोड़ेगा।

शराब पीने वालों को बेलन दिखाएं, उन्हें खाना न दें- मंत्री ने कहा- शराब पीने वालों को महिलाएं बेलन भी दिखाएं। उन्हें खाना बनाकर मत दो। सामाजिक संस्कारों के कारण कई लोग ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन गलत काम रोकने के लिए संस्कार आड़े नहीं आना चाहिए। महिलाएं कम्युनिटी बनाएं। बेलन गैंग बनाएं। भोपाल में शुक्रवार को आयोजित नशा मुक्ति अभियान के एक कार्यक्रम में मंत्री कुशवाह ने शपथ भी दिलाई।

विकसित भारत के लिए नशा मुक्ति जरूरी- मंत्री कुशवाह शुक्रवार को भोपाल में आयोजित नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरुकता कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने वाहन रैली को हरी झंडी दिखाई। साथ ही शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा - मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है। उसमें नशे से मुक्ति दिलाना बहुत जरूरी है। स्वस्थ्य भारत तभी होगा, जब यहां रहने वाला व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ्य होगा। सरकारें अपने कार्यक्रमों के तहत विभिन्न कार्यक्रम चलाती हैं। लेकिन इसमें जब तक जन भागीदारी न हो, तब तक वो कार्यक्रम सफलता हासिल नहीं कर पाता। कई स्वयंसेवी संस्थाएं इस ओर काम कर रही हैं।

रथ यात्रा निकाली, नशा मुक्ति की शपथ ली- नशा मुक्ति के लिए काम करने वाले विभिन्न संगठनों ने रथ यात्रा में भाग लिया। इस अवसर पर कुशवाह ने कहा कि नशे की बुराई को खत्म करने के लिए सभी धार्मिक, आध्यात्मिक संस्थाओं से सहयोग लें।

भोपाल ईडी ने 26.53 करोड़ की प्रॉपर्टी की कुर्क

नारायण निर्यात इंडिया कंपनी पर लिया एक्शन, बैंक से लिया लोन डायवर्ट कर करते रहे खरीदारी

भोपाल (नप्र)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भोपाल ने नारायण निर्यात इंडिया कंपनी और उससे जुड़े दूसरे संस्थानों की 26.53 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को कुर्क किया है। ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की है। इससे पहले सीबीआई भोपाल ने नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर कैलाश चंद्र गर्ग एवं उनके सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया था।

ईडी अफसरों ने बताया- एनएनआईपीएल ने डायरेक्टर कैलाश चंद्र गर्ग एवं अन्य ने यूको बैंक से ग्रुप की विभिन्न कंपनियों के अलग-अलग प्रोजेक्ट के लिए 110.50 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इस लोन अमाउंट का उपयोग एनएनआईपीएल के डायरेक्टर एवं उनके सहयोगियों ने दूसरे प्रोजेक्ट्स में किया। साथ ही लोन में मिली राशि को खुद की सुविधाओं पर खर्च किया। इसके अलावा लोन मंजूर कराने के लिए कंपनी ने फर्जी दस्तावेज बैंक को दिए। यह खुलासा सीबीआई भोपाल की जांच में हुआ था।

जांच रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने एनएनआईपीएल के डायरेक्टर कैलाश चंद्र गर्ग एवं उनके सहयोगियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। केस की जांच में खुलासा हुआ कि बैंक से कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए मंजूर हुई लोन राशि का उपयोग संचालकों ने दूसरे प्रोजेक्ट में किया है। जो मनी लॉन्ड्रिंग है। इसके चलते कंपनी के संचालक गर्ग व अन्य डायरेक्टर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था।

मप्र और महाराष्ट्र में कंपनी की 34 प्रॉपर्टी, सभी कुर्क

ईडी अफसरों ने बताया कि एनएनआईपीएल की मप्र के इंदौर, जौरा, नीमच और महाराष्ट्र के अकोला में कंपनी की अलग-अलग नाम से कंपनी और प्रॉपर्टी है। यह कंपनी और प्रॉपर्टी एनएनआईपीएल के संचालक कैलाश चंद्र गर्ग और उनके सहयोगियों ने यूको बैंक से मिले लोन से बनाई हैं। इसके चलते ग्रुप की मप्र और महाराष्ट्र स्थित 34 प्रॉपर्टी को कुर्क किया है।

10 दिन पहले ईडी ने दर्ज किया था एनएनआईपीएल के खिलाफ केस

ईडी भोपाल के अफसरों ने बताया कि एनएनआईपीएलके डायरेक्टर कैलाश चंद्र गर्ग एवं उनके साथियों के खिलाफ 10 दिन पहले 18 जून को मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। मामले की जांच के बाद गुरुवार देर शाम ईडी ने एनएनआईपीएल की प्रॉपर्टी कुर्क करने की कार्रवाई की है।

भोपाल में सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार

आईपीएल मैनेजर को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप; सरेंडर करने कोर्ट गया था

भोपाल (नप्र)। इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) के एरिया मैनेजर मनोज रघुवंशी (40) सुसाइड केस में आरोपी सब इंस्पेक्टर गौरव रघुवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना के समय गौरव विदिशा कोतवाली के थाना प्रभारी थे। पुलिस ने मनोज की पत्नी ज्योति और साले पिंटू उर्फ देवेंद्र को भी गिरफ्तार किया है। तीनों भोपाल कोर्ट में गुरुवार की दोपहर को सरेंडर करने पहुंचे थे।

अयोध्या नगर टीआई महेश लिल्हारे ने बताया कि तीनों को सरेंडर से पहले कोर्ट के बाहर से पकड़ा है। शाम को आरोपियों को मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश कर तीन दिन की रिमांड पर लिया गया है। तीनों की निशानदेही पर केस से जुड़े अहम सबूत जब्त किए जाना है। इसी के साथ आरोपियों ने फरारी कहां और किस-किस के पास काटी इस संबंध में भी पूछताछ की जाएगी। मामले में 7 लोगों को आरोपी बनाया था। इनमें से गीता रघुवंशी, कांती बाई, टिंकू उर्फ अविनाश और रिटायर्ड एएसआई राम सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है।

गरीब-जरूरतमंदों को मिले सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवाईयों का लाभ : राज्यपाल श्री पटेल

राज्यपाल ने रेडक्रॉस चिकित्सालय में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का किया शुभारंभ

- **चिकित्सालय में डेंटल यूनिट प्रारम्भ, राज्यपाल अनुदान से दी गई 2 डेंटल चेयर**

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा ही प्रभु की सेवा है। जन औषधि केंद्र का ग़रीब और जरूरतमंदों को लाभ मिले। औषधि केंद्र में मिलने वाली सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवाइयों के बारे में प्रचार-प्रसार करें। राज्यपाल श्री पटेल रेडक्रॉस चिकित्सालय में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे।

राज्यपाल श्री पटेल ने शुभारंभ अवसर पर औषधि केंद्र की संचालन गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने औषधि केंद्र में विक्रय की जाने वाली दवाइयों का अवलोकन भी किया। श्री पटेल ने चिकित्सकों से चर्चा करते हुए कहा कि मरीजों को आत्मीय और मनोवैज्ञानिक संबल प्रदान करे। यह मरीजों को शीघ्र लाभ देता है।

नई यूनिट को दी गई 2 डेंटल चेयर

राज्यपाल श्री पटेल ने रेडक्रॉस चिकित्सालय को अनुदान स्वरूप 5 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की है। उन्होंने चिकित्सालय को 2 डेंटल चेयर प्रदान की गई। श्री पटेल ने रेडक्रॉस चिकित्सालय की नई दंत चिकित्सा इकाई का शुभारम्भ किया। उन्होंने नईडेंटल चेयर्स का अवलोकन करते हुए दंत चिकित्सकों से चर्चा भी की।

राज्यपाल श्री पटेल का रेडक्रॉस परिसर में आयोजित प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र के शुभारंभ कार्यक्रम में शॉल और श्रीफल से अभिनंदन किया गया।श्री पटेल ने इस अवसर पर ऑवला और शमी के पौधों का रोपण किया।राज्यपाल श्री पटेल ने रेडक्रॉस प्रबंधन समिति के सदस्यों से मिलकर परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर रेडक्रॉस समिति के चेयरमैन डॉ. गगन कोल्हे और प्रबंधन समिति के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे।

सड़क हादसे में भोपाल की महिला की मौत

मायके से पति के साथ लौट रही थी ससुराल, रास्ते में डंपर ने बाइक को मारी टक्कर

भोपाल (नप्र)। भोपाल की रहने वाली महिला की पिछोर में सड़क हादसे में मौत हो गई। महिला पति के साथ बाइक से गुरुवार की शाम को घर से निकली थी। पिछोर स्थित बांसखेड़ी में बाइक को डंपर ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी थी।

दोनों को वहीं के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। घायल पति और पत्नी को इलाज के लिए परिजन शुक्रवार सुबह हमीदिया अस्पताल ले आए। यहां पत्नी को मृत घोषित कर दिया गया।

लक्ष्मी प्रजापति (19) शंकर नगर छोला की रहने वाली थी। तीन महीने पहले उसकी शादी शुभम राठौर निवासी पिछोर से हुई थी। शादी के बाद बीते एक महीने से वह मायके में मेहमानी में रह रही थी।

उसकी बहन राखी ने बताया कि एक महीने बाद जीजा जी दो दिन पहले भोपाल आए थे। यहां दो दिन तक घूमने फिरने के बाद गुरुवार की शाम को बहन और जीजा बाइक पर सवार होकर घर से निकले थे।

पिछोर स्थित बहन के ससुराल के करीब बांसखेड़ी में डंपर ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। इससे लक्ष्मी गंभीर रूप से घायल हो गई थी।

हादसे की सूचना के बाद रिश्तेदार इलाज के लिए उसे भोपाल लाने के लिए रवाना हुए।

शुक्रवार तड़के सुबह बहन और जीजा को भोपाल ले आए। यहां डॉक्टरों ने चेक कर लक्ष्मी को मृत घोषित कर दिया। रास्ते में ही उसकी मौत हो चुकी थी।

पहली बार ससुराल आया था युवक

मृतका का पति शुभम अपने गांव में खेती किसानी का काम करता है। पहली बार ससुराल में आने के बाद दो दिन तक भोपाल के टूरिस्ट प्वाइंट्स को घूमा। पत्नी को जमकर शॉपिंग कराई। लक्ष्मी को परिजनों ने नम आंखों के साथ गुरुवार को उसे विदाई थी। ससुराल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पिछोर पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी डंपर चालक की तलाश की जा रही है।

पिता बोले- नाश्ते करते हुए कॉल पर बात की थी

मृतका के पिता बने सिंह प्रजापति ने बताया कि बेटी-दामाद ने घर से निकलने के बाद तूमड़ा गांव में चाय नाश्ता किया था। तब बेटी ने कॉल कर जानकारी दी कि हल्की बारिश हो रही है। अच्छा लग रहा है। आसानी से सफर पूरा हो जाएगा। आप लोग परेशान मत होना, इसके बाद सीधे उसकी मौत की खबर आई। ऐसा लग रहा है कि हमारा तो सभी कुछ मिट चुका है। डंपर वाले ने ओवरटेक करने के प्रयास किया था, इससे दामाद की बाइक में टक्कर लग गई।

दिल्ली से भोपाल आने वाली फ्लाइट सवा दो घंटे लेट

भारी बारिश से दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल-1 की छत गिरने से 28 फ्लाइट हुई कैंसिल

भोपाल (नप्र)। दिल्ली से भोपाल आने वाले फ्लाइट शुक्रवार को करीब सवा दो घंटे की देरी से पहुंची। दरअसल, दिल्ली-एनसीआर में बारिश की वजह से शुक्रवार सुबह 5 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर पार्किंग की छत गिर गई। हादसे में कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई, 5 घायल हैं। उड़ान भरने वाली करीब 28 फ्लाइट को निरस्त कर दिया गया।

दिल्ली से भोपाल आने वाली फ्लाइट सुबह 7:30 बजे भोपाल एयरपोर्ट पर लैंड होती है। ये फ्लाइट शुक्रवार सुबह 10:45 बजे लैंड हुई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया- सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए चेक-इन काउंटर्स को बंद कर दिया गया है। दिल्ली आने वाली फ्लाइट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा- एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली फ्लाइट्स समय से आ रही है। भारी बारिश के कारण टर्मिनल 1 के पास एक हिस्सा गिर गया। कुछ लोग घायल हैं। उनकी मदद की जा रही है। उन्हें मेडिकल सहायता दी जा रही है। टर्मिनल 1 से संचालित होने वाली सभी उड़ानों को अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया गया है।

नवनियुक्त संचालक ने राज्य शिक्षा केन्द्र में कार्यभार ग्रहण किया

भोपाल (नप्र)। राज्य शिक्षा केन्द्र के नव नियुक्त संचालक श्री हरजिंदर सिंह ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यालयीन अधिकारियों-कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया और विभागीय कार्यो तथा योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर कार्य प्राथमिकताओं पर जोर दिया।

संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र ने विभागीय सहयोगियों से समयबद्ध और परिणाममूलक कार्यप्रणाली को अपनाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि किसी भी सहयोगी के अच्छे कार्यों की सराहना उसे और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित तो करती ही है, साथ ही दूसरों के लिए प्रेरणा स्त्रोत भी होती है। उन्होंने कहा कि, शिक्षा विभाग के मूल में हमारे शिक्षक और विद्यार्थी हैं, अतः हमारा हर कार्य उनकी बेहतरी के लिए होना चाहिए। हम राज्य स्तर पर कार्य कर रहे हैं, हमारी कार्यप्रणाली ओपन डोर होनी चाहिये, जिससे अन्य सहयोगियों को अपने विचार हम तक पहुँचाने में कोई झिझक या संकोच ना हो। सीखना एक सतत प्रक्रिया है, हमें एक दूसरे से, अन्य संस्थानों से, दूसरे राज्यों और देशों से जहाँ जो अच्छा हो रहा हो, वह सीखना है और उसे अपनी कार्यप्रणाली में अपनाना है।

इस अवसर पर अपर मिशन संचालक श्रीमती आर उमा महेश्वरी, अपर संचालकगण सर्वश्री देवभूषण प्रसाद, पंकज मोहन और शीतांशु शुक्ला सहित सभी नियंत्रक और समन्वयक अधिकारी भी उपस्थित थे।

थाने में बिगड़ी फरियादी की तबीयत, अस्पताल में मौत

सीहोर में पुलिस पर एफआईआर नहीं लिखने का आरोप; एसआई समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड

सीहोर (नप्र)। सीहोर जिले के जावर थाना क्षेत्र में दो पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले। जमीन को लेकर हुए इस विवाद के बाद पीड़ित पक्ष शिकायत करने थाने पहुंचा, यहां उनकी सुनवाई नहीं हुई। मारपीट में घायल एक व्यक्ति की थाने में ही तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।

परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पीड़ित पुलिस पर आरोप लगाते और घायल को अस्पताल ले जाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद एसपी मयंक अवस्थी ने एसआई सहित तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है।

थाने में सुनवाई नहीं होने पर परिजनों ने बनाया वीडियो

जावर तहसील की कल्याणपुरा ग्राम पंचायत के कान्याखेड़ी गांव में गुरुवार रात को दो पक्षों में विवाद हो गया था। गांव में रहले वाले शोभाल सिंह ठाकुर, लखन सिंह, बिजेंद्र सिंह ने चेतन सिंह, बलवान सिंह और अर्जुन सिंह की लाठी डंडों से मारपीट कर दी। इसमें बलवान सिंह और अर्जुन सिंह को चोट आई थी। परिजन घायलों को लेकर रात में ही जावर थाने में एफआईआर कराने के लिए पहुंचे। यहां काफी देर तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। तभी बलवान सिंह की तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे अस्पताल ले गए, वहां बलवान की मौत हो गई। वहीं घायल अर्जुन को अस्पताल में कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि बलवान सिंह की पीट-पीट कर हत्या की गई है। अभी यह क्लियर नहीं है कि मौत की वजह क्या रही। पुलिस ने शव का पीएम कराया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि मौत की वजह क्या है।

जावर थाने के तीन पुलिसकर्मी निलंबित

मारपीट के बाद पीड़ित पक्ष के लोग गुरुवार रात में ही थाने पहुंचे थे। यहां उनकी सुनवाई नहीं हुई। शिकायत के बाद भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। इस आरोप के बाद सीहोर एसपी मयंक अवस्थी ने जावर थाने के एसआई अनिल डोडियार, प्रधान आरक्षक भरत राम और आरक्षक अर्जुन को निलंबित कर दिया है। झगड़े की रिपोर्ट करने आए बलवान की थाने में ही तबीयत खराब हो गई थी। अस्पताल जाने पर बलवान सिंह की मौत हो गई थी। परिजन जावर थाने के पुलिस कर्मियों पर धक्का मुक्की का लगाया आरोप लगा रहे है। एसडीओपी आकाश अमलकर ने तीन पुलिस कर्मियों के निलंबन की पुष्टि की है।

इन लोगों पर एफआईआर

इस मामले में पुलिस ने घायल अर्जुन सिंह की रिपोर्ट पर राम सिंह, शोभाल सिंह सेंधव, लखन सिंह, बिजेंद्र सिंह, पिंटू सेंधव, गोपाल और अर्जुन सेंधव पर हत्या के प्रयास और मारपीट की एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

खेत से कब्जा हटाने का बोला तो कर दी मारपीट

घायल अर्जुन सिंह ने बताया कि मैं अपने भाई चेतन, भतीते पुष्पेंद्र और शुभम के साथ खेत पर था। यहां शोभाल सिंह से खेत की मेड़ को लेकर विवाद था, उसे सुलझाने के लिए बात कर रहे थे। शोभाल सिंह तथा उसके भाइयों ने हमारी जमीन में पत्थर जमा दिए। हमने पत्थर हटाने के लिए कहा तो सोभाल सिंह, लखन सिंह, विजेन्द्र और रामसिंह गालियां देने लगे। गाली देने से मना करने पर सोभाल सिंह, लखन सिंह, विजेन्द्र और रामसिह डंडे लेकर आए और मारपीट करने लगे।

कुछ देर बाद पिंटु उर्फ शिवनारायण, गोपाल सिंह, अरविन्द सिह भी डंडे लेकर आ गए। हमारे साथ मारपीट की। इसमें मेरे सिर पर और कंधे में चोट आई। मेरे भाई पुष्पेन्द ठाकुर को हाथ में शुभम ठाकुर को पीठ पर, चेतन सिंह को हाथ व पीठ पर, बलवान सिंह को हाथ और चेहरे पर चोट लगी। इसके बाद थाने आए तो यहां काफी देर तक सुनवाई नहीं हुई। थाने में ही भाई की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में उनकी मौत हो गई।

कांग्रेस से भाजपा में आईं पार्षद प्रियंका की सीट बदलेगी

भोपाल निगम की मीटिंग में बीजेपी पार्षदों के साथ बैठेंगी; पद से नहीं हटेगी

भोपाल (नप्र)। कांग्रेस से बीजेपी में आई भोपाल के वार्ड-7 से पार्षद प्रियंका मिश्रा की सीट बदलेगी। अब वह बीजेपी पार्षदों के साथ उस लाइन में बैठेंगी, जहां महापौर और एमआईसी सदस्य बैठते हैं। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा- सांसद-विधायकों की तरह निगम में दल-बदल कानून लागू नहीं होता है। इसलिए प्रियंका को पार्षद पद से नहीं हटाया जाएगा।

प्रियंका मिश्रा भाजपा के पूर्व विधायक रमेश शर्मा गुट्टू भैया की बेटी और पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा की बहू हैं। दो साल पहले हुए नगर निगम चुनाव से प्रियंका कांग्रेस के टिकट पर वार्ड-7 की पार्षद चुनी गई थीं। दो महीने पहले मिश्रा बीजेपी में शामिल हो गई थीं।

निगम में कांग्रेस के अब 20 पार्षद

दो साल पहले हुए नगर निगम के चुनाव में 85 में से 22 पार्षद कांग्रेस के जीते थे। सबसे ज्यादा बीजेपी के 58 और निर्दलीय 5 पार्षद थे। कांग्रेस पार्षद मो. सगीर का पिछले साल जुलाई में निधन हो गया था। 6 महीने में हुए उप चुनाव में बीजेपी ने वार्ड से जीत हासिल कर ली थी। इससे कांग्रेस के 21 पार्षद बचे थे। इनमें से एक पार्षद प्रियंका भी बीजेपी में शामिल हो गई। ऐसे में अब निगम में बीजेपी के 20 पार्षद ही बचे हैं।

अध्यक्ष बोले- निगम में दल-बदल कानून लागू नहीं

इस बारे में निगम अध्यक्ष सूर्यवंशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्षद प्रियंका मिश्रा ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। इसलिए अब वे बीजेपी पार्षद के रूप में मीटिंग में शामिल होंगी। नगर निगम में दल-बदल कानून लागू नहीं है।

यह सांसद, विधायकों पर लागू रहता है। इसलिए प्रियंका बीजेपी पार्षदों के साथ बैठ सकती हैं। इससे पहले उन्हें लिखित में आवेदन देना होगा कि उन्हें बीजेपी पार्षदों के साथ बैठने की अनुमति दी जाए। अभी उनका आवेदन नहीं मिला है।नगर निगम की पिछली बैठकों में जिन भी मुद्दों पर विपक्ष ने हंगामा या विरोध किया तो पार्षद प्रियंका मिश्रा भी उनमें शामिल रहीं।

संपादकीय

गुणवत्ता से समझौता क्यों?

क्या देश में राजनीतिक लाभ के लिए गुणवत्ता से समझौते का नया ट्रेंड चल पड़ा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि आज देश के कई हिस्सों में निर्माणाधीन और नवनिर्मित भवन, पुल व सड़कों के गिरने, धंसने अथवा क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसका मुख्य कारण घटिया निर्माण या फिर निर्माण पूरा करने की जल्दबाजी है। ताजा घटना देश की राजधानी नई दिल्ली की है, जहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल एक की छत भारी बारिश के दौरान कई गाड़ियों और टैक्सियों पर गिर गई, जिसमें कुछ लोग दब गए। फिलहाल हवाई अड्डे पर चेक-इन काउंटर बंद करने पड़े और कुछ उड़ानों को भी अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा। बताया जाता है कि शुक्रवार को तेज बारिश के दौरान एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 1 की छत गिर गई। जिसके कारण तीन लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए हैं। हादसे में टर्मिनल की छतों की शीट के अलावा सपोर्ट बीम भी गिर गए जिससे लोगों के पिक-अप और ड्रॉप के लिए आई गाड़ियों भी भारी नुकसान पहुंचा है। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रहे हैं और घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि हाल ही में टर्मिनल-एक का विस्तार किया गया था। इसका उद्घाटन 11 मार्च को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। तब नागर विमानन विभाग ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था। इस हादसे के एक दिन पहले ही मध्यप्रदेश के जबलपुर के डुमना हवाई अड्डे पर 450 करोड़ की लागत से बनी नई इमारत की छत गिर गई। यह कार आयकर विभाग थी। गनीमत रही कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि डुमना एयरपोर्ट पर साढ़े चार सौ करोड़ की लागत से बनी टर्मिनल बिल्डिंग के ड्राप एंड गो एरिया में टेंसिल रूफ फटने से पानी का सैलाब सा आ गया। इसका लोकार्पण भी 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल मोड में किया था। इन घटनाओं से साफ है कि एयरपोर्ट निर्माण में गुणवत्ता का बिल्कुल भी खयाल नहीं रखा गया। ठेके का बड़ा हिस्सा कमीशनखोरी में बंट गया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इन संरचनाओं की गुणवत्ता के बारे में शायद कोई जानकारी नहीं ली। एयरपोर्ट ही क्यों, घटिया निर्माण की कहानी तकरीबन हर जगह है। बिहार में निर्माणाधीन पुलों के गिरने का मानो रिकॉर्ड ही बनता जा रहा है। राज्य के सिवान में गंडक नहर पर बना एक पुराना पुल भरभराकर गिर गया। जिले के दरौंदा प्रखंड के रामगढ़ा पंचायत में बना यह पुल नहर में पानी बढ़ने और कटाव की मार को पुल नहीं झेल सका।

इस पुल के ध्वस्त होने से यहां रहने वाले हजारों लोगो के सामने आवागमन की समस्या खड़ी हो गई है। इसके पहले राज्य के अररिया जिले में भी एक निर्माणाधीन पुल ढहा है जो सुर्खियों में बना हुआ है। और तो और करोड़ों हिंदुओं की आस्था की केन्द्र अयोध्या में निर्माणाधीन राम लला के मंदिर में पानी रिसने की जानकारी मिली थी। हालांकि मंदिर प्रशासन का दावा रहा है कि गलतियां ठीक कर ली गई है। हमेशा की तरह इन तमाम हादसों की भी जांच के आदेश हो चुके हैं। जांच कमेटियों की देर सवेर रिपोर्टें भी आएंगी। लेकिन ऐसी जांच में कोई दोषी साबित होगा, होगा भी या नहीं, यह कौन नहीं जानता। इसका मुख्य कारण भयंकर भ्रष्टाचार है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने, निर्माण के लिए जमीनों का अधिग्रहण करने, मुआवजा बंटने, निर्माण कार्य में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने, हर मामले में सबकी मुख्य रूचि कमीशन खाने और निर्माण कार्य की गुणवत्ता न होना इसका बड़ा कारण है।

नजरिया

डॉ. सुधीर सक्सेना

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

सुरेश गोपी यानि केरल में खिला कमल

केरल के सर में अंततः सर्रासज (कमल) खिल गया। हाल के चुनाव में त्रिशूर लोकसभा क्षेत्र में सुरेश गोपी क्या जीते, भारतीय जनता पार्टी की मुराद पूरी हो गयी। बीजेपी को यह कामयाबी लंबे बेचैन इंतजार के बाद नसीब हुई, जिसने इसकी महत्ता और मिठास को बढ़ा दिया। केरल वह राज्य है, जहां विश्व के इतिहास में प्रथम निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार ईएमएस नंबूद्रीपाद के नेतृत्व में सन 50 के दशक में सत्तारूढ हुई थी। दूसरे केरल ऐसा राज्य है, जहाँ की राजनीति दो विरोधी गठबंधनों की धूरी पर टीकी हुई है। केरल की राजनीति में सेंध लगाने और पांव टिकाने के लिये बीजेपी ने तरह-तरह के दांव आजमाये, लेकिन बात बनी नहीं। अंततः आजादी के अमृत काल में उसे सफलता मिली और केरल के चुनावी इतिहास में पहली बार उसके उम्मीदवार ने किसी एक किले पर जीत का परचम लहराया।

केरल की राजनीति में वामपंथ और प्रगतिशीलता शुरू से केन्द्र में रही है। साक्षरता में अव्वल इस प्रदेश का मिजाज सेक्यूलर है और वह सांप्रदायिकता ध्रुवीकरण को धता बताते हुए उनके ध्वजवाहक संगठनों को ठेंगा बताता रहा है। चुनाव-दर- चुनाव बीजेपी के लिए केरल में अंगूर खट्टे रहे। न तो बिस्कुट किंग राजन पिल्लै की पत्नी नीना पिल्लै को चुनाव लड़ाने से बात बनी और न ही मेट्रो मैन श्रीधरन पर दांव लगाना काम आया। मगर इस पूरे दौर में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व केरल मे संभावनाओं को लेकर जबदस्त होमवर्क करता रहा। उसी दरम्यान उसकी नजर सुरेश गोपी पर पड़ी। मलयाली फिल्मों का यह चमकीला सितारा बीजेपी नेतृत्व को मिशन-केरला के लिए सर्वथा उपयुक्त लगा। बीजेपी को केरल में किसी पापुलर चेहरे की तलाश थी। उसने रणनीति तैयार की। उसे लागू करने में सतर्कता बरती। फलतः सुरेश गोपी बीजेपी के पाले में आ गये और 'प्रथम ग्रासे मक्षिका पातः' के पहले चुनावी हादसे से उबरकर उन्होंने सन् 2024 के ग्रीष्म में कांग्रेस का परंपरागत किला त्रिशूर सर कर लिया।

25 जून, सन् 1958 को अलपुझा में जनमें सुरेश के. गोपीनाथन पिल्लै और ज्ञानलक्ष्मी अम्मा की संतान है। उनका बचपन कोल्लम में बीता। प्राथमिक शिक्षा स्थानीय कॉन्वेंट के उपरांत फातिमा माता नेशनल कालेज में हुई। जीव विज्ञान में स्नातक उपाधि के बाद उन्होंने अंग्रजी साहित्य में एमए किया। फिल्मों से उनका नाता जुड़ने का सबब यह रहा कि पिता फिल्मों के वितरक थे। उससे बालक सुरेश में फिल्मों के प्रति लगाव उपजा। अभिनय की पहली सीढ़ी उन्होंने सात साल की उम्र में चढ़ी। सन् 1965 में उन्होंने ओडायिल निन्नू में बाल कलाकार की भूमिका निभायी। सन् 1986 में वयस्क होने पर उनके लिए फिल्मों के द्वार खुल गये और बाद के वर्षों में उन्होंने मुख्यतः मलयाली और कुछेक तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में तरह-तरह की भूमिकाएं निभायी और सफलता के झंडे गाड़े।

उनकी कई फिल्में बॉक्स आफिस पर हिट रहीं और उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किये। अपने असमाप्त फिल्मी करियर में सुरेश झोपी अब तक ढाई सौ से

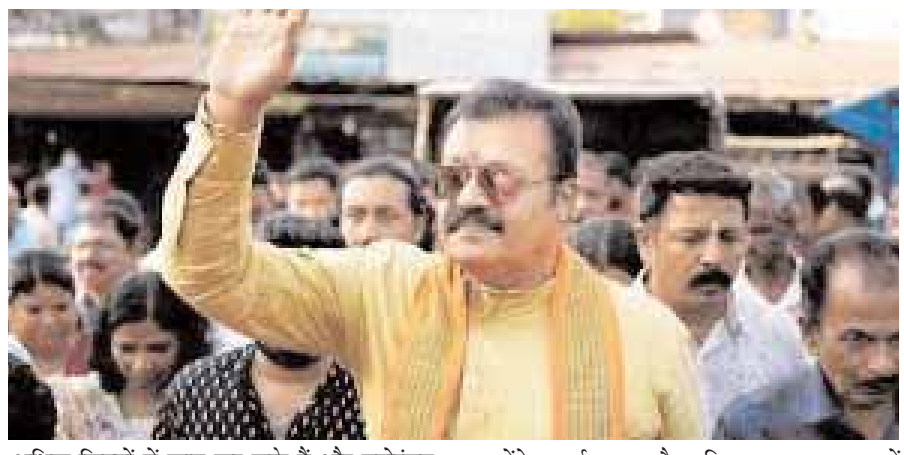

अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं और मनोरंजन को रुपहली दुनिया में अभिनेता और पार्श्व गायक के अलावा टीवी होस्ट के तौर पर उभरे हैं। सन् 1998 में उन्हें फिल्म 'कालियट्टम' के लिये क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर का सिने अवार्ड मिल चुका है।

सुरेश गोपी की सफल और लोकप्रिय फिल्मों की फेहरिश्त लंबी है। सन् 1987 में 'उरुपथमनुट्टांडु' में खलनायक की भूमिका में वह चर्चित रहे। लेकिन उनकी कामयाबी में चार चाँद सन् 90 के परवर्ती दशक में लगे। यह दशक उनकी बेशुमार शोहरत का दशक था। उन्हें दर्शकों का बेतहाशा प्यार और सम्मान मिला। लेखक रेंजी और निदेशक शाजी की जोड़ी की जुगल बंदी से आई फिल्में अभिनेता सुरेश गोपी को खूब फली। थलस्तानम, एकलव्यन और माफिया जैसी फिल्मों ने उन्हें मलयाली सिने दर्शकों की चहेता कलाकार बना दिया। बड़ी बात यह कि सुरेश किसी एक रोल में टाइप्ड नहीं हुये, बल्कि उन्होंने तरह-तरह की भूमिकाएं निभायी। वह चरित अभिनेता रहे और नायक और खलनायक भी। यहां तक कि उन्होंने हास्य भूमिकाएँ भी निभायी। मणिचित्रयाजू में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। सन 90 के परवर्ती दशक में आई उनकी नकुलन, काश्मीरम, कमिश्नर, हाईवे, राजपुत्रन, लेलम आदि ने धूम मचा दी। जनपतिपथयम, गुरू, प्रणयवरनंगल, तलोलम, पथरम, वझुन्नोर, मार्क एंटोनी, कवर स्टोरी, मकलक्कू, मेघ संदेशम, भारत चंद्रन आईपीएस आदि से यह सिलसिला और आगे बढ़ा। इसके बाद कुछ वर्ष के लिए सुरेश ने फिल्मों से फासला बरता, लेकिन सन् 2006-15 के दरम्यान उनकी फिल्मों को आशातीत सफलता नहीं मिली। उन्होंने एकबारगी संन्यास भी लिया, लेकिन सन् 2019 में तमिलारासन (तमिल) और मार्क एंटोनी के जरिये उन्होंने जबर्दस्त कमबैक किया। सन 2020 में 'वराने अवश्यमुंड' में सुरेश और शोभना की जोड़ी करीब 15 साल बाद एक साथ दिखी। तरता पाप्पन, काबूल कर गुरूदन जैसी फिल्मों ने उन्हें पुनः मलयाली सिने परिदृश्य के केंद्र में ला दिया।

8 फरवरी, सन 1990 को राधिका नायर से विवाहित गोपी सदृहस्थ कलाकार है। कौन यकीन करेगा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ सीपीआई (एम) की युवा ईकाई एसएफआई से किया था। इसके बाद उनका लगाव कांग्रेस से रहा। श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रशंसक वह कल भी थे और आज भी हैं। त्रिशुर से चुने जाने के बाद श्रीमती गांधी को 'मदर इंडिया' कहना अकारण या आकस्मिक कतई नहीं है। वह उदारमना सदाशयी नेता हैं। सन 2006 के असेंबली चुनाव में उन्होंने नयी मिसाल कायम की। उन्होंने पोन्नानी में यूडीएफ के गंगाधरन का प्रचार किया तो मलमपुझा में एलडीएफ के अच्युतानंदन का। केरल में पहले पहल और इकलौता कमल खिलाने वाले सुरेश गोपी का कमल से रिश्ता एक दशक पुराना भी नहीं है। उन्होंने अक्टूबर, सन् 2016 में बीजेपी ज्वाइन की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कहने पर उन्होंने सन् 2021 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। लेकिन सीपीआई के पी. बालाचंद्रन से वह चुनाव हार गये। दिलचस्प बात यह है कि मतों की गणना में वह तीसरी पायदान पर रहे। बालाचंद्रन की मुख्य प्रतिद्वंद्वी रहीं कांग्रेस की पद्मजा वेणुपाल। इससे पहले हुआ था सन 2019 का लोकसभा चुनाव। गोपी त्रिशुर से लड़े, लेकिन कांग्रेस के टीएन प्रतापन ने उन्हें मात दे दी। दौड़ में वह तीसरे स्थान पर रहे। प्रतापन के मुख्य प्रतिद्वंदी रहे भाकपा के राजाजी मॅथ्यू थामस। ऐसा लगता है कि अपनी शख्सियत के बूते सुरेश गोपी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नजरों में चढ़ गये और उन्होंने केरल में बीजेपी की डोंगी खेने का दायित्व गोपी को देने का फैसला किया। सुरेश गोपी 29 अप्रैल, सन् 2016 को राज्यसभा के लिए मनोनीत हुये और 24 अप्रैल, 22 तक उच्च सदन के सदस्य रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अनेक महत्वपूर्ण कमेटियों का सदस्य मनोनीत किया। 4 जून को चुनाव 24 के नतीजे आने के कुछ ही दिनों बाद पीएम ने उन्हें मंत्री पद से नवाजा। उन्हें पेट्रो रसायन और पर्यटन मंत्रालयों में राज्यमंत्री बनाया गया। मंत्री बनने के तुरंत बाद उन्होंने पहला काम यह किया कि इसरो के चेयर मैन एस. सोमनाथ से मिले और मुल्लापेरियार तथा इडुक्की बांधों से संबंधित बाढ़ की विभीषिका के संदर्भ में अंतरिक्ष-प्रोद्योगिकी के उपयोग पर चर्चा की।

सुरेश गोपी संप्रति केन्द्रीय मंत्री हैं, किंतु उनकी रुचि मंत्री पद में नहीं है। वह सांसद रहकर अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहते हैं। उनकी भाषा शालीन है और आचार-विचार में वह उदारता बरतते हैं। यही वजह है कि उन्हें पूर्व सीएम और माकपा नेता (स्व.) ई के नयनार के परिजनों से मिलने और पूर्व सीएम तथा कांग्रेस नेता (स्व.) के करुणाकरण की समाधि पर मत्था टेकने में संकोच नहीं होता । इससे भाजपा नेताओं में भले ही बेचैनी फैले, लेकिन केरल में बीजेपी को पांव पसारने के लिए गोपी सरीखे नेताओं की जरूरत है। उन्हें चर्च जाकर 'नन्नी चोल्लुन्नू दैवम' (प्रभु तेरा शुक्रिया) कहने अथवा मुसलमानों की रोजा इफ्तार में शिरकत से परहेज नहीं है। 21 प्रतिशत ईसाईयों और 14 प्रतिशत मुसलमानों की आबादी के केरल में गोपी बीजेपी की जरूरत बनकर उभरे हैं। क्योंकि उनके प्रशंसकों में कम्युनिस्ट भी हैं और काँग्रेसी भी। ऐसे राज्य में जहाँ बीजेपी के वोट गत 25 वर्षों में 6.56 फीसद से बढ़कर 16.68 फीसद हो गये हों, गोपी का होना बीजेपी के लिए सोने पे सुहागा है।

मुद्दा

अली खान

लेखक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार में शिक्षक हैं।

स्वच्छ और सुरक्षित फुटपाथ क्यों है जरूरी?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि जब प्रधानमंत्री या कोई वीआईपी आता है, तो सड़कों और फूटपाथ को एकदम चकाचक कर दिया जाता है। यदि एक दिन यह हो सकता है, तो सभी लोगों के लिए ऐसा हर रोज क्यों नहीं हो सकता। आखिरकार, नागरिक टैक्स देते हैं और साफ-सुथरे और सुरक्षित फूटपाथ पर चलना उनका मौलिक अधिकार है। बता दें कि जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस कमल खता की खंडपीठ ने कहा कि सुरक्षित और स्वच्छ फुटपाथ मुहैया कराना राज्य प्राधिकरण का दायित्व है। राज्य सरकार के केवल यह सोचने से काम नहीं चलने वाला कि शहर में फुटपाथ घेरने वाले अनधिकृत फेरीवालों की समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। राज्य सरकार को अब इस दिशा में कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने शहर में अनधिकृत रेहड़ी-पटरी वालों की समस्या पर पिछले वर्ष स्वतः संज्ञान लिया था। पीठ ने कहा कि उसे पता है कि समस्या बड़ी है, लेकिन राज्य व नगर निकाय सहित अन्य अधिकारी इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। यह एक मौलिक अधिकार है। हम अपने बच्चों को फुटपाथ पर चलने को कहते हैं, लेकिन अगर चलने को फुटपाथ ही नहीं होंगे तो हम उनसे क्या कहेंगे?

इस बीच आम-आदमी के मस्तिष्क में इस सवाल का कौंधना स्वाभाविक है कि आखिर मूल अधिकार से क्या अभिप्राय है? दरअसल, मूल अधिकार ऐसे अधिकारों का समूह है जो किसी भी नागरिक के भौतिक (सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक) और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। इसके साथ ही मौलिक अधिकार किसी भी देश के संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को दी गई आवश्यक स्वतंत्रता और अधिकारों के एक समूह को संदर्भित करते हैं। ये अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आधारशिला को भी निर्मित करते हैं तथा नागरिकों की राज्यों के मनमाने कार्यों एवं नियमों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये अधिकार बुनियादी मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करते हैं। एक राष्ट्र के भीतर लोकतंत्र, न्याय और समानता को

बनाए रखने के लिए ये अधिकार संविधान का अभिन्न अंग है। इन अधिकारों को मौलिक अधिकार माना जाता है, क्योंकि ये व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास, गरिमा और कल्याण के लिए आवश्यक हैं। इनके असंख्य महत्व के कारण ही उन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। ये अधिकार संविधान द्वारा गारंटीकृत और संरक्षित हैं, जो कि देश के मूलभूत शासन को संदर्भित करते है।

दरअसल, आज हकीकत यह है कि शहरी भारत में पैदल चलने के लिए वर्तमान में कई बाधाओं और रुकावटों से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण अक्सर किसी की सुरक्षा को जोखिम में डालना पड़ता है। यहां तक कि कभी-कभी किसी की जान भी जोखिम में पड़ जाती है। भारतीय शहरों में पैदल यात्रियों की उपेक्षा केवल पैदल यात्रियों की सुविधाओं को कम प्राथमिकता देने और उनके खराब क्रियान्वयन का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक बड़े प्रणालीगत मुद्दे का भी प्रतिबिंब है। दरअसल, भारत में पैदल यात्रियों के लिए कानूनी अधिकारों और उपायों की व्यापक व्यवस्था का अभाव। यह स्थिति विशेष रूप से बुजुर्गों या बच्चों जैसे कमजोर समूहों के लिए खतरनाक है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय पैदल यात्रियों के लिए कानूनी सुरक्षा अपर्याप्त है। हालांकि कानूनी तौर पर, पैदल चलने वालों को सुरक्षा प्रदान करने वाले कुछ रास्ते हैं, जिनमें मोटर वाहन अधिनियम (1988) और भारतीय दंड संहिता (1860) शामिल है, जो पैदल चलने वालों को जोखिम में डालने वाले मोटर चालकों द्वारा लापरवाही से वाहन चलाने पर दंड का प्रावधान करता है। इसके अलावा सड़क विनियमन नियम (1989), जो पैदल चलने वालों के संबंध में मोटर चालकों की जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड विधेयक (2010) बोर्ड को राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन से संबंधित महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों और पैदल चलने वालों के लिए विशेष आवश्यकताएं प्रदान करने का अधिकार देता है। इन सभी के बावजूद भारतीय पैदल यात्रियों के लिए कानूनी सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए बड़े पैमाने पर सुधार अपेक्षित है।

आज कमोबेश देश के सभी शहरों की अधिकांश सड़कों पर अतिक्रमण का बोलबाला है। अतिक्रमण के चलते फूटपाथ गुम हो गए हैं। इस पर जनता का अधिकार है। मौजूदा वक्त में फुटपाथ की समस्या बहुत बड़ा नासूर बन चुकी है। यह बेहद चिंताजनक बात है कि इस समस्या का आज तक कोई स्थाई समाधान नहीं हो सका है। लिहाजा, सरकार को चाहिए कि वह जनता के लिए स्वतंत्र और सुरक्षित फुटपाथ मुहैया करवाए। हालात कुछ इस प्रकार है कि देश के सभी शहरों के प्रमुख बाजारों में वाहन पार्किंग की समस्या के कारण लोग फुटपाथ और सड़कों पर गाड़ी पार्क करने के लिए मजबूर है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि शहरों में पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त हो। ताकि कोई भी व्यक्ति वाहन पार्किंग स्थल के अभाव में फुटपाथ पर गाड़ी खड़ी करने के लिए विवश न हो। साथ ही देखा गया है कि शहरों में विभिन्न प्रकार के विज्ञापन बैनरों को फुटपाथ पर रख दिया जाता है, जिससे पैदल यात्रियों को दिक्कतें झेलनी पड़ती है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि फुटपाथ पर बैनर लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ताकि आम-आदमी बड़ी आसानी से फुटपाथ का इस्तेमाल कर सके, साथ ही उसके जीवन को किसी भी प्रकार के जोखिम से बचाया जा सके।

समय परीक्षाओं की परीक्षा का

कटाक्ष

केदार शर्मा

लेखक व्यंग्यकार हैं।

यह समय परीक्षाओं की परीक्षा का है। खेत को सुरक्षित रखने के लिए बाड़ का लगाया जाना जरूरी है। पर जब बाड़ ही खेत को खाने लग जाए तो तो ऐसी बाड़ और उसमें सेंध लगाने वाले ऐसे अतिक्रमी तंत्र और लोक दोनों के लिए चुनौती है,जिनका ध्येय वाक्य ही यह है कि नीति पर चलते हुए असफलता को स्वीकार नहीं करेंगे,अनीति पर चलकर येन-केन प्रकारेण सफलता का अपहरण करके ही रहेंगे।

एक के बाद एक परीक्षाओं के पर्चे लीक होने के बनते रिकार्ड से यह बात तो सिद्ध हो गई है कि इस देश में प्रतिभाओं की कतई कमी नहीं है। प्रतिभाएँ लीक से हटकर काम करती है।भारतेंदु हरीश्चंद्रजी ने एक स्थान पर सही लिखा था-'लीक लीक गाड़ी चले,लीकहि चले सपूत,बिना लीक तीनों चले सायर,सिंह, कपूत। 'वर्षों से पढ़ना,पढ़ना और पढ़ना, बस...।और फिर भी गारंटी नहीं कि लीक पर चलती गाड़ी नौकरी की नाव में बैठा ही दे। जिनके पास सिंह जैसा साहस था, सायर यानि चतुरता के भंडार थे,(भले ही आप उनको कपूत कहें,) उन्होनें नवाचार किया और सात कोठों में बंद पेपर को लीक कर पूरे में से पूरे मार्क्स ले आए। जेल और जुर्माना भी जिनके दृढ़ निश्चय को हिला नहीं पाया,हर स्तर पर कसा सुरक्षा प्रहरियों का शिकंजा कसा का कसा रह गया। कभी पुलिस भर्ती की, कभी सबइंस्पेक्टर भर्ती की, आए दिन अध्यापकों की भर्ती की और अब जनता के दूसरे भगवान यानि चिकित्सकों की परीक्षा समेत देश भर की करीब इकतालीस परीरक्षाओं को एक के बाद ये फेल करते गए। ऐसे प्रतिभाशालियों में प्रतिभा होने से भला कैसे इंकार किया जाए ?

अब आप यही कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग किया है। यह हमारे सिस्टम की कमी हो सकती है कि इनकी प्रतिभा का उपयोग सही जगह नहीं किया गया। जो करोड़ों रूपए खर्च कर रखी गई गोपनीयता में सेंध लगा सकते हैं, मौका मिलता तो क्या वे अपने शत्रु देशों की खुफिया सूचनाओं को लीक कर जासूसी में अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं कर सकते थे? गैंगस्टरों की,नक्सलवादियों, आतकंवादियों की खुफिया जानकारी लीक नहीं कर सकते थे ? अपेक्षाकृत पेपर लीक से कम कठिन ऐसे कामों को तो ये शायद चुटकियों में अंजाम दे सकते थे। अब भी जो मास्टर माइंड सिद्ध हो चुके हैं उनको बिना परीक्षा, बिना इंटरव्यू जासूस के तौर पर सी.बी.आई. जैसे महकमों में भर्ती करने पर विचार किया जाना चाहिए।

पकड़ में आए मास्टर माइंड से किसी ने पूछा-'क्या आपको अपने किए का पश्चोताप हैं? वह बोला-'अंकलजी,पश्चांताप इस बात का है कि हमने पेपर लीक की उस नाव का,जिसमें हम सब सवार थे,उस छेद को बंद नहीं किया जिसमें से लीक की सूचना लीक हो गई। हमारी किस्मत भी बेहद खराब निकली । अगर आप यह सोचते हैं कि पिछले दो-पाँच सालों से ही पेपर लीक होने लगे हैं तो यह आपका अनुमान गलत हो सकता है। पहले भी चुपचाप न जाने कितने शख्सल ऐसे ही सरकारी 'नावों' पर सवार हो चुके होंगे, न जाने कितने सही सलामत 'नाव' से उतरकर किनारे लग गए होंगे,और आराम फरमा रहे होंगे? अखबार में हमारी असफलता की खबरे पढ़कर हँस रहे होंगे। बहुत से किनारे लगने के करीब होंगे। यह घुणाक्षर न्याय है ही ऐसा कि इसमें जो पकड़ में आए सो चोर है। पर ईमानदार तो वे भी नहीं थे जो आज तक पकड़ में नहीं आए हैं। यह किस्मत भी पिछले दो-पाँच सालों से धोखा देने लगी है। इससे पहले चुपचाप काम हो जाता होगा। तभी शोरगुल नहीं मचता होगा। बेकायदा साँप भी मरता होगा और लाठी भी नहीं टूटती होगी। फिर बीच में एक दौर आया कि साँप मरने लगा,भले ही लाठी टूट जाती थी। अब हालात यह है साँप भी नहीं मरता और बाकायदा लाठी भी टूटती है। मीडिया और सरकार पूरी तरह से चाकचौबंद हो गए हैं। सचमुच हम दया के पात्र हैं, हमें दुख है कि हम पेपर लीक करने की सूचना को लीक होने से नहीं रोक पाए,अन्यथा बातें एक होती न दो।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

संपादक - उमेश त्रिवेदी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)

RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

राजेंद्र बज

इतिहास हमसे मत पूछो....

धुंआ एवं धूल उड़ाते हुए भारी भरकम ट्रक मेरी डुगडुगी को ओवरटेक करते हुए आगे निकल गया। मैं दांत पीसकर रह गया। एकाएक ट्रक के पिछले हिस्से पर लिखी हुई इबारत 'इतिहास हमसे मत पूछो' पर नजर पड़ी। इस पर मैं सहम कर रह गया। अंदेशा होने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि में ट्रक वाले से पंगा ले लूं और फिर वह मेरे इतिहास के बल पर मेरे वर्तमान एवं भविष्य पर ही प्रश्नचिन्ह लगा दे। मैं कोई राजनीतिज्ञ तो था नहीं जो अपने इतिहास से होने वाली छिछालदारी को विरोधियों का कुप्रचार करार देते हुए अपनी शर्मिंदगी को भी शर्मिंदा कर सकूं। न ही मैं सरकार का अधिकृत नुमाइंदा हूं ,जो भ्रष्टाचार के बड़े से बड़े आरोपों को भी गुलाब जामुन की तरह गटक सकूं।

मैं ठहरा एकदम आम भारतीय की भांति, जो इतना भावुक होता है कि चुनावी दौर में नेता के गिड़गिड़ाने की तो छोड़ो , अपितु एक छल भरी मुस्कुराहट को भी निश्चल मुस्कान मानकर उसके प्रति आसक्त हो जाता हो। यहां तक कि देश-प्रदेश की सत्ता तक को उसके हवाले कर सकता हो। जब कभी न्याय के लिए फरियाद भी करना हो तो जाने-अनजाने किस्म के 'अपराध बोध' से ग्रस्त अवस्था में फरियाद करने के लिए जमाने भर का साहस जुटाना पड़ता हो। ऐसे में जब कभी ऐसा सुनने को मिले कि 'इतिहास हमसे मत पूछो', तो सच कहूं, ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह जाया करती है। इतना जरूर है कि किसी बात पर गुस्सा आने पर मुंह बंद करके दांत जरूर पीस लिया करता हूं।

आजकल इतिहास को लेकर बड़े चर्चे हैं। कोई कहता है इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। और कोई यह कहता है कि इतिहास से छेड़छाड़ कर हमारी संस्कृति से खिलवाड़ किया जा रहा है। वैसे इतिहास यह भी कहता है कि जो आज है, वह कल वह नहीं था -जो आज है। इस बात को लेकर आदिकालीन भारतवासियों को कभी पराया बताया जाता है तो कभी अपना बताया जाता है। अब यह जो अपना-पराया की बात है, एक प्रकार से वर्तमान दौर की सियासत का नया संस्करण है। जो है, वह नहीं है जो कि है और जो नहीं है, वह नहीं है जो कि वह है। इस भूल-भुलैया में मैं भी शेष आम नागरिकों की भांति भौचक्का होकर सियासत के करतब देखा करता हूं। मूल बात 'इतिहास' को लेकर उठती है और इतिहास पर ही जाकर समाप्त होती है।

बचपन में सुना था कि हमारे पूर्वज बंदर थे। इस पर मैंने सवाल किया था कि बंदर थे तो आज पूंछ कहां हैं ? इस पर सुनने को मिला था कि पूंछ का कोई उपयोग नहीं था, इसलिए वह घिसते-घिसते घिसा गई। तब तो बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि आदमी की 'पूछ' ही कहां रह गई है ? बहुत संभव है कि बीती शताब्दियों में सियासत के कर्णधारों ने हमारे पूर्वज बंदरनुमा आदमियों की पूंछ पकड़-पकड़ कर ऐसा नाच नचाया होगा कि पूंछ का अस्तित्व ही शेष न रहा। खैर, सोचते-सोचते इतनी सारी जमाने भर की बातें मनोमस्तिष्क में उछलकूद कर रही थी कि एक और ट्रक ओवरटेक कर गया। जिसके पिछले हिस्से पर लिखा हुआ था कि 'हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे।' अब मैं मुकाम पर आ गया था। खैर।

बीते कुछ समय से तत्कालीन स्थापित राजनेताओं के इतिहास को लेकर नाना प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं। जिसके चलते इन नेताओं के होते सोतो को जवाब देना भारी पड़ रहा है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि धरती का सीना चीरकर दिवंगत आत्मा पूर्व शरीर धारण कर प्रकट हो, या कि आसमान से उतर कर आए -और अपना बचाव कर सके या सफाई दे सके। यही कारण है कि राजनीति में जी -भरकर गढ़े मुर्दे उखाड़े जाने का सिलसिला निरंतर परवान चढ़ रहा है। जहां तक मेरा सवाल है तो मैं राजनीति में रुचि इसलिए भी नहीं लेता कि कुलदीपक के अभाव में आने वाले दौर में यदि मेरी थुक्काफाजिती हुई, तो उसका खंडन मुंडन और अंतिम संस्कार कौन करेगा ? इसके चलते आखिर स्वर्ग में या नर्क में सुख-चैन से भी कैसे रह पाऊंगा ?

राजनीति

अनिल ठाकुर

हार का मंथन व जीत की विवेचना आवश्यक

मंथन की इसी प्रक्रिया से लम्बे समय के बाद बीजेपी गुजर रही है ।एनडीए के बहुमत में आने के बावजूद गठबंधन के मुख्य घटक दल बीजेपी को यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों में बड़ा नुकसान हुआ, नतीजन पिछले दो चुनाव में अकेले बहुमत के आंकड़े को पार करने वाली पार्टी इस बार 242 के आंकड़े पर आकर अटक गई।इसी वजह से मप्र, छग, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे राज्यों में उसे आशा से अधिक मिली सीटें और समर्थन की महत्ता कम हो गई ।यूपी में अपेक्षा के विपरीत इतनी कम सीटे मिलने से इस हार को पहाड़ जैसा बना दिया। अब मंथन से क्या निकलेगा यह तो अगस्त के प्रथम सप्ताह में ही पता चलेगा । लेकिन हार के कारणों के साथ जीत के कारक पर भी मंथन होना चाहिए, तभी सही निष्कर्ष सामने आ पायेगें।

परंपरा है कि प्रत्येक राजनीतिक पार्टी हार के कारणों पर मंथन करती है। लेकिन क्या निष्कर्षों के अनुरूप नीतियों में बदलाव लाती है? अधिकांश बार जवाब ना में ही आयेगा। यह पहली बार हुआ है कि राष्ट्रीय चुनाव में अलग अलग राज्यों में राज्य स्तरीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दों के मुकाबले ज्यादा कारगर हुए। मजेदार तथ्य यह है कि एक गठबंधन के बहुमत में आने एवम सरकार बनाने के बावजूद दूसरा गठबंधन अपनी जीत बताते हुए इस तरह का आचरण कर रहा है मानो उसने सिंहगढ़ किला जीत लिया हो। यह सब जानते है कि हार या जीत के असली कारण क्या है, लेकिन जीत का श्रेय हर कोई लेना चाहता है, पराजय की जिम्मेदारी लेने का साहस कोई नही करता।

मंथन की इसी प्रक्रिया से लम्बे समय के बाद बीजेपी गुजर रही है। एनडीए के बहुमत में आने के बावजूद गठबंधन के मुख्य घटक दल बीजेपी को यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों में बड़ा नुकसान हुआ, नतीजन पिछले दो चुनाव में अकेले बहुमत के आंकड़े को पार करने वाली पार्टी इस बार 242 के आंकड़े पर आकर अटक गई। इसी वजह से मप्र, छग, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे राज्यों में उसे आशा से अधिक मिली सीटें और समर्थन की महत्ता कम हो गई। यूपी में अपेक्षा के विपरीत इतनी कम सीटे मिलने से इस हार को पहाड़ जैसा बना दिया। अब मंथन से क्या निकलेगा यह तो अगस्त के प्रथम सप्ताह में ही पता चलेगा। लेकिन हार के कारणों के साथ जीत के कारक पर भी मंथन होना चाहिए, तभी सही निष्कर्ष सामने आ पायेगें। दस वर्षो के बाद बीजेपी के इस स्थिति में पहुंचने के असली कारणों को समझना है तो मंथन 2018 में मप्र, राजस्थान, और छग की विधान सभा में पराजय से शुरू होना चाहिए। इन राज्यों में पराजय के बाद ही उतार चढ़ाव आए। इन्हीं राज्यों में सिर्फ छह बाद ही लोकसभा चुनाव में भारी समर्थन मिला था। ब्रांड मोदी, रणनीति, संघ की भूमिका, पन्ना एवं बूथ प्रमुख सभी की सक्रियता दोनों चुनावों में थी, फिर छह माह में ही इतना बड़ा उलटफेर कैसे? यदि उस समय विधान सभा में हार के बाद जीत के कारणों का सही आकलन किया होता तो आज यह नौबत नहीं आती। बंगाल में लोकसभा के अच्छे प्रदर्शन एवम विधान सभा में पराजय के बाद लोकसभा चुनाव में भी खराब प्रदर्शन, यूपी विधान सभा के अप्रत्याशित नतीजे, 2019 लोकसभा चुनाव में असाधारण उपलब्धि, हिमाचल एवम कर्नाटक में पराजय के कुछ ही माह बाद मप्र, राजस्थान और छग में भारी विजय जैसे नतीजों के बाद इस बार लोकसभा में भारी नुकसान लिए बहुत गहरे अध्ययन एवं पड़ताल की जरूरत है। तभी ब्रांड मोदी, मुद्दे, पन्ना एवं बूथ प्रमुखों, कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता, राज्य क्षत्रपों, संघ की भूमिका, धुर्वीकरण, जातिवाद एवम साथी दलों की सोच का सही आकलन हो सकेगा । सभी राज्यों में जीत और हार के कारण अलग अलग रहे है। ऊपर से नीचे तक सभी को आईने में झांकने की जरूरत है। बीजेपी

के लिए आंतरिक मूल्यांकन के अतिरिक्त इस बार साथी दलों को साधे रहने की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह आशंका भी है कि मोदी को पार्टी के अंदर से चुनौती मिल सकती है। संघ के साथ संबंधों को लेकर इस धारणा को बल मिला है। विपक्ष से कांग्रेस तो उन्हें चैन से बैठने नही देगी, लेकिन केंद्र में स्थायित्व एवम विधान सभा चुनाव की दृष्टि से शरद पंवार, ममता बनर्जी और मायावती के रुख उनके लिए ज्यादा तकलीफ दायक हो सकते है।

ऐसा न हो कि अपनी जिम्मेदारी दूसरो पर डाल देने से उन मतदाताओं के हितों को भुला दिया जाय जो अब तक बिना अपना स्वार्थ देखे समर्थन करता आया है। एक वर्ग आरक्षण से वंचित, टैक्स देने के बावजूद महंगाई से जूझता, अपने युवा होते बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित है, जो आज तक मोदी के पक्ष में खड़ा है। सहन शक्ति की एक सीमा होती है, तुष्टिकरण कही भी हो एक समय के बाद नुकसानदायक होता है।

मंथन की जरूरत इंडी गठबंधन को भी है लेकिन वे तो इसे अपनी जीत बता रहे है। गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस के लिए तो हार, जीत के मायने सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार है। बीजेपी के कई दिग्गजों की हार हुई है , लेकिन क्या इंडी गठबंधन विशेष रूप से कांग्रेस को दिग्विजयसिंह, नकुलनाथ, वैभव गहलोत, भूपेश बघेल के नाम भी याद है। क्या कांग्रेस ने एंटोनी कमेटी के निष्कर्षों को स्वीकार किया था ? दस वर्षो तक सत्ता से बाहर रहने एवं तीसरी बार भी अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के बावजूद कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण एवम सनातन संस्कृति की अनदेखी की नीति में कोई परिवर्तन करने को तैयार नहीं। दोनों गठबंधन के क्षेत्रीय दलों के क्षत्रप अपनी सफलता से खुश है, सिवाय तेजस्वी और अजीत पंवार के।

एक समय था जब नतीजों को स्वीकार कर विपक्ष दूसरे दिन से अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए उद्यत हो जाता था। कुछ क्षेत्रों में मत पेटियां लूटने, क्षेत्र के विपक्षी मतदाताओं को डराने धमकाने जैसे किस्से उस समय सामान्य थे। लेकिन कभी हौवा नही बन पाए। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी येन केन प्रकारेण बेमतलब बहस का क्या औचित्य है ?

एक स्वस्थ लोकतंत्र की धारणा को मजबूत करते हुए, मतदाता ने दोनो पक्षों को चेतावनी देते हुए सावधान कर दिया है, कौन कितनी गंभीरता से लेता है यह आने वाला वक बताएगा।

सरोकार

निरमा

शिक्षा के लिए संघर्ष करतीं किशोरियां

राज्य के अजमेर जिला स्थित नाचनबाड़ी गांव ऐसा ही एक उदाहरण है. जिला के घूघरा पंचायत स्थित इस गांव में अनुसूचित जनजाति कालबेलिया समुदाय की बहुलता हैं. पंचायत में दर्ज आंकड़ों के अनुसार गांव में लगभग 500 घर हैं. गांव के अधिकतर पुरुष और महिलाएं स्थानीय चूना भट्ठा पर दैनिक मज़दूर के रूप में काम करते हैं. जहां दिन भर जी तोड़ मेहनत के बाद भी उन्हें इतनी ही मज़दूरी मिलती है जिससे वह अपने परिवार का गुज़ारा कर सके. यही कारण है कि गांव के कई बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं आसपास के गांवों से भिक्षा मांगकर अपना गुज़ारा करते है. समुदाय में किसी के पास भी खेती के लिए अपनी ज़मीन नहीं है. खानाबदोश जीवन गुज़ारने के कारण इस समुदाय का पहले कोई स्थाई ठिकाना नहीं हुआ करता था. हालांकि समय बदलने के साथ अब यह समुदाय कुछ जगहों पर पीढ़ी दर पीढ़ी स्थाई रूप से निवास करने लगा है. लेकिन इनमें से किसी के पास ज़मीन का अपना पट्टा नहीं है. इस समुदाय में बालिका शिक्षा की स्थिति अब भी कम है.

हमारे देश में महिलाओं और किशोरियों को आज भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पितृसत्तात्मक समाज से संघर्ष करनी पड़ती है. कभी आधुनिकता और कभी संस्कृति एवं परंपरा के नाम पर उसके पैरों में बेड़ियां डालने का काम किया जाता रहा है. शिक्षा, हर रुकावट को दूर करने का सबसे सशक्त माध्यम है. लेकिन महिलाओं और किशोरियों के सामने इसी क्षेत्र में सबसे अधिक बाधा उत्पन्न की जाती है. उन्हें पढ़ने और सशक्त बनने से रोका जाता है. भले ही शहरी क्षेत्रों में अब किशोरियों के लिए शिक्षा प्राप्त करने में रुकावटें हटने लगी हैं, लेकिन देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष करनी पड़ती है.

2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के मामले में देश में जो तीन सबसे कमजोर राज्य हैं उनमें राजस्थान भी है. जहां साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत 74.04 प्रतिशत की तुलना में केवल 67.06 प्रतिशत है. ऐसे में यहां महिलाओं में साक्षरता की दर का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है और बात जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय में महिलाओं के साक्षरता दर की करेंगे तो यह आंकड़ा और कितना कम होगा, यह पता लगाना बहुत अधिक मुश्किल नहीं होगा.

राज्य के अजमेर जिला स्थित नाचनबाड़ी गांव ऐसा ही एक उदाहरण है. जिला के घूघरा पंचायत स्थित इस गांव में अनुसूचित जनजाति कालबेलिया समुदाय की बहुलता हैं. पंचायत में दर्ज आंकड़ों के अनुसार गांव में लगभग 500 घर हैं. गांव के अधिकतर पुरुष और महिलाएं स्थानीय चूना भट्ठा पर दैनिक मज़दूर के रूप में काम करते हैं. जहां दिन भर जी तोड़ मेहनत के बाद भी उन्हें इतनी ही मज़दूरी मिलती है जिससे वह अपने परिवार का गुज़ारा कर सके. यही कारण है कि गांव के कई बुज़ुर्ग पुरुष और महिलाएं आसपास के गांवों से भिक्षा मांगकर अपना गुज़ारा करते है. समुदाय में किसी के पास भी खेती के लिए अपनी ज़मीन नहीं है. खानाबदोश जीवन गुज़ारने के कारण इस समुदाय का पहले कोई स्थाई ठिकाना नहीं हुआ करता था. हालांकि समय बदलने के साथ अब यह समुदाय कुछ जगहों पर पीढ़ी दर पीढ़ी स्थाई रूप से निवास करने लगा है. लेकिन इनमें से किसी के पास ज़मीन का अपना पट्टा नहीं है. इस समुदाय में बालिका शिक्षा की स्थिति अब भी कम है.

हालांकि पहले की तुलना में कालबेलिया समुदाय के लोग अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने लगे हैं लेकिन अधिकतर लड़कियों की 12वीं के बाद शादी कर दी जाती है. इस संबंध में समुदाय की एक 37 वर्षीय महिला शांति बाई बताती हैं कि 'नाचनबाड़ी में केवल एक प्राथमिक विद्यालय है, जहां पांचवी तक की पढ़ाई होती है. इसमें गांव के सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं. लेकिन इसके आगे के लिए बच्चों को तीन किमी दूर घूघरा जाना पड़ता है. जहां अपनी लड़कियों को भेजने के लिए अभिभावक तैयार नहीं होते हैं.' शांति बाई बताती हैं कि उनकी तीन लड़कियां हैं जो 10वीं, 9वीं और 6वीं में पढ़ने के लिए घूघरा गांव जाती हैं. यह समुदाय की पहली लड़कियां हैं जो 5वीं से आगे शिक्षा प्राप्त करना शुरू की थी. उनके इस कदम से समुदाय के कुछ जागरूक अभिभावकों ने भी अपनी लड़कियों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए घूघरा गांव के हाई स्कूल में एडमिशन कराया है.

शांति बाई की बड़ी बेटी रौशनी जो 10वीं की छात्रा है, बताती है कि उसे और उसकी बहनों को पढ़ना अच्छा लगता है. इसलिए वह प्रतिदिन स्कूल जाती हैं. वह बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है. लेकिन स्कूल में विज्ञान के शिक्षक का पद खाली है, इसलिए वह घर में इस विषय की तैयारी करती है. रौशनी की बात को आगे जोड़ते हुए शांति बाई कहती हैं कि वह लोग आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं. उनके पति स्थानीय चूना भट्ठा पर दैनिक मज़दूर के रूप में काम करते हैं. जिसमें इतनी ही मजदूरी मिलती है जिससे परिवार का किसी प्रकार गुजारा हो सके. इसके बावजूद वह अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहती हैं. वह कहती हैं कि उनके समुदाय के उत्थान के लिए सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं, जिसका लाभ उठाकर समुदाय विकास कर सकता है. लेकिन जागरूकता के अभाव में ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है. ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि रौशनी और उसकी बहनों जैसी नई पीढ़ी शिक्षित होकर एक दिन समुदाय की सोच और दशा अवश्य बदलेगी.

वहीं 48 वर्षीय सदानाथ कालबेलिया बताते हैं कि उनके समुदाय में शिक्षा के प्रति अभी भी बहुत अधिक जागरूकता नहीं आई है. अधिकतर लड़के 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर परिवार के साथ मजदूरी करने निकल जाते हैं या फिर ताश और जुआ जैसे बुरे कामों में लिप्त हो जाते हैं. माता-पिता भी उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं. ऐसी परिस्थिति में लड़कियों की शिक्षा के बारे में यह समुदाय कहां सोचेगा? वह कहते हैं कि कालबेलिया समुदाय की अधिकतर लड़कियां 5वीं से आगे पढ़ नहीं पाती थी. हालांकि अब इसमें थोड़ा बहुत बदलाव आ रहा है और अब कुछ माता-पिता लड़कियों को पांचवीं से आगे पढ़ाने के लिए दूसरे गांव भेजने लगे हैं. लेकिन यह रुझान बहुत अधिक नहीं है. लेकिन अगर नाचनबाड़ी गांव में ही 10वीं और 12वीं तक के स्कूल खुल जाएं तो शायद इस दिशा में प्रगति हो सकती है.

वह बताते हैं कि उनके दो बेटे और तीन बेटियां हैं. जिन्हें वह पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन लड़कियों की शिक्षा के प्रति समाज की नकारात्मक सोच इस दिशा में सबसे बड़ी बाधा बन रही है. विशेषकर जब घर के ही बड़े बुजुर्ग लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने की जगह उनकी शादी करने का दबाव डालने लगें तो अभिभावकों के सामने विकट परिस्थिति आ जाती है. ऐसी परिस्थिति का वह स्वयं सामना कर रहे हैं. लेकिन शिक्षा की महत्ता को समझते हुए वह अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने का प्रयास करेंगे.

इस संबंध में स्थानीय समाजसेवी वीरेंद्र बताते हैं कि कालबेलिया समुदाय में शिक्षा के प्रति जागरूकता अभी कम है. यही कारण है कि इस समुदाय की कोई भी लड़की आज तक 12वीं से आगे की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकी है. दसवीं के बाद से ही कालबेलिया समाज की ओर से माता-पिता पर लड़की की शादी कराने का दबाव बढ़ने लगता है. हालांकि इस समुदाय में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से बहुत अधिक प्रयास किए जाते रहे हैं. इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम संचालित करती हैं. लेकिन यह सभी प्रयास उस समय ही सफल हो सकते हैं, जब सरकारी पहल और इन संस्थाओं के साथ मिलकर कालबेलिया समाज आगे बढ़ेगा. इसके लिए समुदाय में जागरूकता का प्रसार करनी होगी ताकि इस समाज की किशोरियों को शिक्षा जैसे मूलभूत अधिकार के लिए संघर्ष न करनी पड़े. (चरखा फीचर)

पुस्तक समीक्षा

रमेश कुमार 'रिपु'

समीक्षक

विसंगतियों के प्रतिरोध का स्वर है 'भरे पेट की भूख'

यह किताब सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों को आधार बनाकर लिखा गया है। डॉ प्रदीप उपाध्याय का यह दसवां व्यंग्य संग्रह है। उन्होंने देश,राजनीति और समाज की घटनाओं को लघु कथा के रूप में ढाल कर टिप्पणियां की है। विसंगतियों के प्रतिरोध के स्वर की गूंज हर व्यंग्य में है।'भरे पेट की भूख' की रचनाएं अपने समय और परिवेश के अलावा सरकारी व्यवस्था, राजनीति एवं समकालीन मनुष्य की समस्याओं से रूबरू कराती है।

इस संकलन में राजनीति और व्यवस्था से जुड़ी रचनाएं अधिक हैं।राजनीति में अंध भक्त का चलन चौकाता है। अंध भक्त अपने अराध्य में अवगुण नहीं देखता। वह केवल अनुसरण करता है। उसी तरह राजनीति में है। 'आज की विक्रम वैताल कथा' शीर्षक की रचना से स्पष्ट है, कि आज की राजनीति में हर कोई बलि का बकरा ढूंढ लेता है। अपनी गलती का ठिकरा किसी और पर फोड़ने का चलन चल पड़ा है। नये संसद भवन में शेर की मूर्ति को लेकर बहुत बवाल मचा था । लेखक ने 'शेर बहुत कंफ्यूजन में है' के जरिये लोगों की सोच पर तंज कसा है। मैंने शेरों से पूछा, कि शेर साहब,आप जब सारनाथ में सौम्यता की मूर्ति बने रहे तो अब संसद भवन में आपको अपने मूल स्वरूप में आने की क्या जरूरत पड़ गयी। एक शेर ने कहा,कैसे आदमी हो तुम। तुम भी विपक्षियों की भाषा में बात कर रहे हो। तुम खुद ही सोचो,जहां सत्य अहिंसा की बात हो वहां कोई शेर कैसे दहाड़ सकता है।

एक पॉकेट व्यंग्य में लेखक कहता है,देखो व्यंग्यकार,जिस तरह से व्यंग्यकार का छपास रोग ठीक नहीं हो सकता,ठीक उसी तरह राजनीतिज्ञों का सत्ता रोग ठीक नहीं हो सकता। दूसरी पार्टी से आए लोगों को जब तवज्जो नहीं मिलती तो किस तरह थाली में छेद कर देते हैं,इसकी बानगी है 'कितने आदमी थे'। डॉ प्रदीप उपाध्याय अपनी रचनाओं में चिंतनशील नजर आते हैं। सरकारी काम दुनिया के आश्चर्य से कम नहीं हैं। कई बार पुलिया बन जाती हैं पर दिखाई नहीं देती है।तालाब खुद जाते हैं,मगर दिखते नहीं। यानी कह सकते हैं,कि सरकारी काम आश्चर्य पैदा करने के लिए ही होते हैं। जहां पुलिया की जरूरत नहीं है,वहां पुलिया बन जाती है। बिजली है

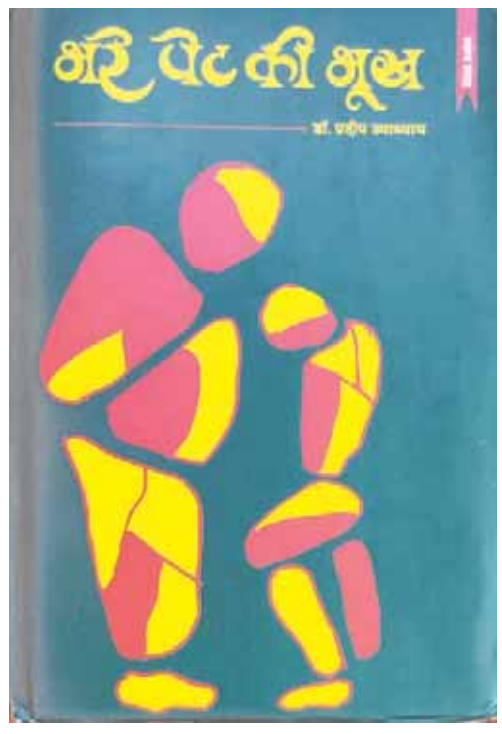

नहीं,पर नल जल योजना से लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं। सरकारी कार्यो की व्यवस्था को आइना दिखाया गया है 'गजब उनके काम और गजब उनके तौर तरीके' शीर्षक वाली रचना में। देश में ईडी के छापे से पता चला कि किस -किस नेता के पास भ्रष्टाचार का पैसा है। 'हाय पैसा वाह पैसा' से लेखक ने बताया कि पैसा थक सकता है,मगर इंसान नहीं। सिकंदर ने ताबूत के बाहर अपना खाली हाथ दिखा कर दुनिया का बताया,कि सब कुछ यहीं रह जाता है। कोई लेकर नहीं जाता। बावजूद इसके पैसे की चाहत आदमी की जाती नहीं। 'बाबूजी को ठंड क्यों लगती है' के बहाने जीवन की सच्चाई की ओर इंगित किया गया है कि ढलती उम्र में यह सब स्वाभाविक है।

'भरे पेट की भूख' संग्रह में सैतालिस व्यंग्य रचनाएं हैं। व्यवस्था की जवाबदेही जिन पर है वे कैसी-कैसी टुच्ची हरकतें करते हैं,उसका तीखा चित्रण इस संग्रह में है। लेखक ने अपनी टिप्पणियों में लेखकीय नजर का भरपूर इस्तेमाल किया है। पेपर लीक होने की घटनाओं पर रोक लगाने का जो उपाय बताया गया है, वो तरीका भविष्य में सरकार करने लगे तो आश्चर्य नहीं। 'न रहेगी परीक्षा,न होंगे लीकेजेस' व्यवस्था की लापरवाही का दस्तावेज है। जो बताती है,कि वो दिन दूर नहीं है,जब सरकारी पद भी ठेके पर सरकार देने लगेगी, ताकि परीक्षा लीक के झंझट से बच सकें। इस किताब में छोटे- छोटे व्यंग्य के जरिये कई सवाल उठाए गए हैं। उन सवालों की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

चूंकि लेखक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं,इसलिए इस संग्रह में ज्यादातर रचनाओं में उसकी तपिश है। 'भरे पेट की भूख' रचना सरकारी अव्यवस्था की सच्चाई है। लाख दावा सरकार करे, कि मुफ्त राशन बांटकर किसी को भूखा नहीं रहने दिया गया। सरकारी राशन भूखे पेट तक पहुंचा या फिर निजी राशन दुकान तक। इसे देखने वाली आँखें सरकारी व्यवस्था के पास नहीं है। इस समय विश्व गुरू की बात खूब हो रही है। उसका मजाक भी उढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है,कि आदमी भले गांव का हो लेकिन अपना वैश्विक स्तर चाहे तो ऊंचा कर सकता है। न्यूयार्क नहीं गया है,मगर कह सकता है,कि अगले माह न्यूयार्क जा रहा हूं । गांव के लोग अपने कार्यक्रम को अन्तरराष्ट्रीय नाम देकर बढ़ा कर रहे हैं।

अपने इर्द गिर्द के जीवन की हलचल पर तीखी टिप्पणी से अंत तक पाठक को यह किताब बांधे रखती है।

किताब - भरे पेट की भूख
लेखक - डॉ प्रदीप उपाध्याय
प्रकाशक - किताब गंज
कीमत -350 रुपए

जन परिषद का 35वां वार्षिक समारोह 30 जून को

जन परिषद के समारोह में शिरकत करेंगी मिस यूनिवर्स

बैतूल। भोपाल में होने वाले अग्रणी संस्था जनपरिषद के 35वां वार्षिक समारोह सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ऋषि शुक्ला, वरिष्ठ रंगकर्मी एवं सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राजीव वर्मा, पूर्व डीजीपी डीपी खन्ना, पूर्व डीजीपी एन के त्रिपाठी, पूर्व डीजीपी महान भारत सागर, पूर्व आईएएस अजात शत्रु श्रीवास्तव, एसके मिश्रा, मनीष श्रीवास्तव, जीपी श्रीवास्तव, आईएफएस अखिलेश अर्गल, मिस यूनिवर्स टाइटैनिक ब्यूटी आशिता कोचर, मिसेज यूनिवर्स टाइटैनिक ब्यूटी प्रगति सेठ एवं मिसेज वर्ल्ड वाइड भूमिका सिंह की विशिष्ठ उपस्थिति में आगामी 30 जून को शाम चार बजे स्टेट म्यूजियम श्यामला हिल्स में आयोजित किया गया है। जन परिषद के महासचिव अजय श्रीवास्तव नीलू के अनुसार इस अवसर पर कुछ उपलब्धि प्राप्त व्यक्तित्वों को सम्मानित भी किया जाएगा।

गणित विषय में 100 प्रतिशत परीक्षा परिणाम देने वाले व्याख्याता हुए रिटायर, किया सम्मान

बैतूल। देहगुड़ व्याख्याता श्री तिलक सोले की अपनी 9 वर्षों की शासनसेवा पूर्ण कर आज रिटायर हो गये। इस मौके पर शिक्षकों, बच्चों, व ग्रामवासियों ने पुष्पमाला, शॉल श्रीफल, स्मृतिचिन्ह कर कर उन्हें सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि अधिकांश वर्षों के उनका परीक्षा इनके दयारा पढ़ाये जाने वाले गणित विषय का परीक्षा परीणाम 100 प्रतिशत प्रथम रहा है और उच्चअधिकारियों द्वारा सम्मानित किया जाता रहा है। विद्यालय के लिए 5 एकड जमीन एक भूमि का स्व. कीमती कलसिया बाई अफरलाल आड़े का स्मरण कर नमन किया गया। वहीं भी सोलंकी व्याख्याता द्वारा विद्यालय परिसर के लिए 50 ट्री गार्ड डेकर पौधरोपण किया गया तथा उन्हें विकसित कने का संकल्प लिया गया। कार्यबृद्ध में विशेष अतिथि एक्सीलेंस प्राचार्य भी एस-पचोरी, विद्यालय के प्रार्थाय की आर के इवे शिक्षक, शिक्षिकाएँ, छात्र, अधिकावक, ग्रामवासी अनेक संस्थाओं के प्रकारी प्रालाय, समाजसंगम समाज संगठनों के पदाधिकारी, प्रतिनिधी उपस्थित रहे।

बलवा करने वाले 2 पक्षों का पुलिस ने रस्सी से बांधकर निकाला शहर में जुलूस

मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी के निर्देश पर हुई 151 की कार्यवाही

बैतूल। बीच सड़क पर लॉ एन आर्डर की धज्जियां उड़ाने वालों को एसपी के निर्देश पर सबक सिखाया गया है। कोतवाली पुलिस ने मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद तत्काल एक्शन लिया और चार आरोपियों को हिरासत में लेकर बकायदा जुलूस भी निकाला।

आरोपियों के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट सहित 151 की कार्यवाही की गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बुधवार इटारसी रोड पर दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद जमकर हाथापाई हुई थी। बीच सड़क पर हो रहे तमाशे के बाद लोगों में भय की स्थिति भी व्याप्त हो गयी थी।

आरोपी खुलेआम हाथों में हथियार लेकर गुंडई कर रहै थे। गुरुवार इस बलवे का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी निश्चल एन झारिया ने एक्शन लेकर कोतवाली पुलिस को कार्यवाही के निर्देश दिए। जिसके बाद चार युवकों को कोतवाली पुलिस ने आनन फानन में पकड़ा लिया। इन आरोपियों के हाथ रस्सी से बांधकर जुलूस निकालते हुए कोतवाली थाने लाया गया। बताया जा रहा है कि एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस की इस कार्यवाही से बदमाशों में हड़कम्प मचा है।

करियर काउंसलिंग योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रित

बैतूल। मध्य प्रदेश शासन की करियर काउंसलिंग योजना के अंतर्गत जिला रोजगार कार्यालय के माध्यम से इच्छुक आवेदकों को कैरियर संबंधी मार्गदर्शन देने हेतु काउंसलर्स की टीम गठित की जानी है। काउंसलरों के पैनल हेतु करियर मार्गदर्शन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्ति जिला रोजगार कार्यालय बैतूल में 5 जुलाई तक आवेदन दे सकते है।

जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि काउंसलर्स की टीम में एक मनोवैज्ञानिक के अलावा मार्गदर्शन हेतु तीन विषय विशेषज्ञ रहेंगे, जो प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी एवं मार्गदर्शन देंगे। काउंसलर्स को नियमानुसार मानदेय दिया जाएगा। काउंसलर्स के पैनल में मनोवैज्ञानिक हेतु आवेदन के लिए मनोवैज्ञानिक में स्नातकोत्तर डिग्री या पीजी डिप्लोमा अनिवार्य है। विषय विशेषज्ञ हेतु आवेदन के लिए एडमिशन तथा स्कॉलरशिप प्रवेश, प्रतियोगी परीक्षा एवं रोजगार प्रशिक्षण के क्षेत्र में मार्गदर्शन, परामर्श देने का अनुभव तथा योग्यता रखना अनिवार्य है। आवेदन संबंधी अन्य जानकारी हेतु जिला रोजगार कार्यालय में कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।

जिले में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर ने की समीक्षा

विधायकों ने कहा बैतूल का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

बैतूल। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा गुरुवार को शासन की योजनाओं की विभागवार प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में माइनिंग, जिला शिक्षा केन्द्र, जल निगम, शिक्षा, ऊर्जा, जल जीवन मिशन, कृषि, राजस्व एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों के अपडेट से कलेक्टर को अवगत कराया गया।

इस अवसर पर बैतूल, विधायक हेमंत खंडेलवाल, भैंसदेही विधायक महेंद्र सिंह चौहान, मुलताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख, घोड़ाडोंगरी विधायक श्रीमती गंगा बाई उइके, आमला विधायक डॉ.योगेश पंडाग्रे उपस्थित थे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षत जैन ने जिले की विभागवार उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

राजस्व प्रकरण निराकृत किए- जिले में अविवादित नामांतरण में 68.61 प्रतिशत प्रकरण निराकृत किए गए। इसमें सर्वाधिक 100 प्रतिशत निराकरण के साथ आमला में प्रथम स्थान पर रह। मुलताई में 91.18 प्रतिशत एवं भैंसदेही 83.50 प्रतिशत निराकरण के साथ तृतीय स्थान पर रहा। विवादित नामांतरण में मुलताई, शाहपुर एवं मासोद तहसील 100-100 प्रतिशत निराकरण के साथ प्रथम स्थान पर रहे। इनमें गत वर्ष 349 प्रकरण लंबित थे। जबकि चालू वर्ष में 49 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए थे।

बंटवारा प्रकरणों के निराकरण- अविवादित बंटवारा प्रकरणों के निराकरण में आठनेर, आमला और घोड़ाडोंगरी में 83.35, 83.33 एवं 78.26 प्रतिशत के साथ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर है। इनमें 1173 प्रकरण गत वर्ष के लंबित थे और 580 प्रकरण चालू राजस्व वर्ष में पंजीकृत किए गए है। गत वर्ष 129 प्रकरण विवादित बंटवारे के थे। जिनमें तहसील मुलताई की साईखेड़ा वृत्त 100 प्रतिशत निराकरण के साथ प्रथम स्थान पर रहा। तहसील मुलताई और तहसील आठनेर 75 एवं 65.38 प्रतिशत के साथ द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे।

137 अरब के अर्थदण्ड अधिरोपित- खनि शाखा द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के दर्ज प्रकरण में रेत उत्खनन के कुल 8 प्रकरण अवैध परिवहन के 32 एवं अवैध भंडारण के 10 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें एक अरब 38 करोड़ 48 लाख 05 हजार 407 रूपए के अर्थ दंडा प्रस्तावित किया गया। राजस्व वसूली में रायल्टी से वित्तीय वर्ष 2020-24-25 में निर्धारित लक्ष्य 100 करोड़ के विरूद्ध 14.09 करोड़ राशि माह जून 2024 तक प्राप्त की गई। इसके अलावा ग्रामीण अधोसंरचना तथा सडक विकास से 18 करोड़ के विरूद्ध 5.26 राजस्व शुल्क के रूप में वूसली की गई।

उपरोक्त के अलावा अन्य विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष की लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धियों को पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत की गई। इनमें स्कूल शिक्षा, ऊर्जा एवं जल संसाधन विभाग द्वारा अपनी उपलब्धियों पर प्रस्तुति दी गई।

नल-जल योजना- जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले में 2 लाख 65 हजार 872 परिवारों का लक्ष्य रखा गया था। इसमें 2 लाख 8 हजार 195 घरेलू नाम कनेक्शन प्रदान किए गए। लक्ष्य के विरूद्ध 78.31 प्रतिशत हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान किया गया। एकल ग्राम नल जल योजना के अंतर्गत 1096 ग्राम स्वीकृत है। इनमें समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत 220 ग्राम के लिए स्वीकृति प्रदान है। ओवर लेप श्रेणी में 325 ग्राम रखे गए है। बताया गया कि नल जल योजना में शेष 57 ग्रामों में कार्य प्रगति पर है।

अब अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर से लिंक होगी जिला अस्पताल की सोनोग्राफी मशीन

अस्पताल में सोनोग्राफी करवाने आने वाले लोगों को राहत मिलेगी

बैतूल। जिला पिछले 6 महीनों से बिना रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर के संचालित हो रहा है। जिला अस्पताल में सोनोग्राफी करने आ रहे गरीबों को वापस लौटना पड़ रहा है। केवल गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी हो रही है। अब राहत की बात यह है कि जिला अस्पताल की सोनोग्राफी को इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल से लिंक किया जाएगा। सीधे इंदौर हॉस्पिटल से विशेषज्ञ सोनोग्राफी की रिपोर्ट ऑनलाईन देंगे।

इस सेवा के शुरू होने से अस्पताल में सोनोग्राफी करवाने आने वाले लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि अभी इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन अस्पताल में ही सोनोग्राफी की सुविधा शुरू हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि जिला अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट डॉ ओपी यादव दिसम्बर 2023 में रिटायर हो गए। इनके रिटायरमेंट के बाद से इनके स्थान कोई नए डॉक्टर की पदस्थापना नहीं हुई है।

अस्पताल प्रबंधन ने महिला डॉक्टर को ट्रेनिंग देकर गर्भवती महिलाओं की इमरजेंसी सोनोग्राफी करवाई जा रही है। अन्य दूसरे लोगों की सोनोग्राफी अस्पताल में नहीं हो रही है। जो भी व्यक्ति सोनोग्राफी के लिए अस्पताल पहुंचता है, उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अब व्यवस्था बनाना शुरू किया है।

इस तरह से होगी सोनोग्राफी- सीएमएचओ डॉ रविकांत उईके ने बताया कि मुलताई के एक धर्माधिकारी के सहयोग से जिला अस्पताल की सोनोग्राफी मशीन को इंदौर के अरविंदो मेडिकल कॉलेज से ऑनलाईन जोड़ा जाएगा। स्थानीय कर्मचारियों को भी इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। जिला अस्पताल की सोनोग्राफी मशीन जब अरविंदो हॉस्पिटल से जुड़ जाएगी तो यहां के डॉक्टरों के माध्यम से अस्पताल में सोनोग्राफी सुविधा शुरू होगी। अरविंदो मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ डॉक्टर की सोनोग्राफी की रिपोर्ट ऑनलाईन तुरंत प्रदान करेंगे। इसके लिए ऑनलाइन एक प्रोजेक्टर भी लगाया जाएगा।

जिसके माध्यम से सोनोग्राफी के माध्यम से डॉक्टर इंदौर हॉस्पिटल से लाइव देखकर सोनोग्राफी करवाएंगे। इस सेवा के शुरू हो जाने से जिलेवासियों को सोनोग्राफी की समस्या से राहत मिल सकती है। गत दिनों अरविंदो हॉस्पिटल के संचालक डॉ विनोद भंडारी ने जिला अस्पताल बैतूल आकर व्यवस्था को देखा था। अरविंदो हॉस्पिटल की तरफ से ही बारिश के बाद मुलताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कैंसर उपचार शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर को लेकर भी तैयारियां चल रही है।

इनका कहना

जिला अस्पताल की सोनोग्राफी मशीन को ऑनलाईन निजी अस्पताल से जोड़ा जाएगा। निजी अस्पताल के डॉक्टरों के माध्यम से ऑनलाईन सोनोग्राफी होगी और रिपोर्ट भी मिलेगी। जिससे रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर की कमी को पूरा किया जाएगा। निजी अस्पताल के डॉक्टर जिला अस्पताल को सहयोग करने के लिए तैयार है।

- डॉ रविकांत उईके, सीएमएचओ, बैतूल

बदमाशों ने सुरक्षा टीम पर किया पथराव, पत्थरबाजी में टूटा एंबुलेंस का कांच, बाल- बाल बचे सुरक्षाकर्मी

बैतूल। सारणी में बदमाशों ने सुरक्षा टीम पर पथराव कर दिया। पत्थरबाजी में एम्बुलेंस का कांच छतिग्रस्त हो गया है। दरअसल सारणी खदान में लूट, डकैती, पत्थरबाजी, मारपीट और चोरी जैसी वारदात आम हो चली। बदमाशों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद होते जा रहे हैं कि अब अलग-अलग गिरोह बनाकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। खास बात यह है कि एक, दो नहीं,

बल्कि कई बार चोर, बदमाशों के गिरोह सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। लेकिन मुंह पर कपड़ा बंधा होने की वजह से पहचान नहीं हो पा रही। यही वजह है कि डब्ल्यूसीएल और पुलिस विभाग चोरों के गिरोह पर नियंत्रण नहीं पा रहे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात 10से 20 नकबजन हथियारबंद चोर छतरपुर टू कोयला खदान के परिसर में घुस आए। जिन्हें देखकर कार्य पर मौजूद सुरक्षा गार्ड्स के होश उड़ गए। सुरक्षा गार्ड्स ने बिना समय गंवाए इसकी सूचना पेट्रोलिंग टीम और पुलिस को दी। गश्ती दल को देख कुछ चोर स्क्रैप लेकर भाग निकले तो कुछ स्क्रैप छोड़कर भाग गए। इसी दौरान जब चोरों और गश्ती दल का आमना सामना हुआ तो चोरों ने हवा फायरिंग का जवाब पत्थरबाजी से दिया। पत्थरबाजी में छतरपुर टू खदान परिसर की एंबुलेंस का कांच तक टूट गया है। चोर, पुलिस व सुरक्षा गार्ड्स के बीच यह कोई पहली मुठभेड़ की घटना नहीं है। इसके पहले भी इस तरह की वारदातें वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पाथाखेड़ा क्षेत्र में हो चुकी हैं।

साइबर सुरक्षा बड़ी चुनौती, बच्चों का सचेत रहना जरूरी : एसपी श्री झारिया

आरडी पब्लिक स्कूल में पुलिस विभाग ने आयोजित की साइबर सुरक्षा कार्यशाला

बैतूल। उत्कृष्टशैक्षणिक संस्थान आरडी पब्लिक स्कूल बैतूल में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देने के साथ-साथ उनके बहुमुखी विकास के लिए समय-समय पर समसामयिक विषयों पर केन्द्रित कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। जिसमें विशेषज्ञों, अधिकारियों, वैज्ञानिकों द्वारा विद्यार्थियों को संबंधित विषय की महत्वपूर्ण जानकारी से रूबरू कराया जाता है। आरडी पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर श्रीमती ऋचा खण्डेलवाल की पहल पर पुलिस विभाग द्वारा 28 जून को स्कूल में साइबर सुरक्षा कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक बैतूल निश्चल झारिया ने विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा की विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में एसपी निश्चल

झारिया ने कहा कि तकनीकि के इस दौर में साइबर सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि बच्चों को साइबर जोखिमों से सचेत रहना अत्यंत जरूरी है।

साइबर सुरक्षा के गुर सिखाये- पुलिस विभाग बैतूल द्वारा आरडी पब्लिक स्कूल बैतूल में आयोजित कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक श्री झारिया ने छात्र-छात्राओं को साइबर सुरक्षा के गुर सिखाये। उन्होंने विभिन्न साइबर अपराधों के उदाहरण देकर उनकी पहचान करने और सुरक्षा की विस्तार से जानकारी दी। एसपी ने विद्यार्थियों को उपयुक्त पासवर्ड का चयन करना, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग और अन्य ऑनलाइन सुरक्षा सूत्रों के बारे में अवगत कराया। एसपी ने कहा कि हमारा प्रयास अधिक से अधिक बच्चों को साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूक करने का है जिससे वे अपनी ऑनलाईन गतिविधियों को सुरक्षित रख सके।

अच्छी बारिश के लिए शुरू हुए टोटके, ग्रामीणों ने शिवलिंग को पानी में डुबोया

बैतूल। मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक देदी है, अब सभी को अच्छी बारिश का इंतजार है। दरअसल पिछले एक माह से रुक रुककर हो रही बरसात को लेकर किसान परेशान हैं क्यूंकि वे खेतों में बुवाई कर चुके हैं। देखने में ये आया है की आसमान में काले बादलों की मौजूदगी के बावजूद मृग नक्षत्र पूरा निकल गया बरसात नहीं हो रही।

भोलेनाथ को पानी में डूबो दिया- ग्राम खेड़ी सावलीगढ़ के ग्रामीणों ने स्थानीय गंगा कुंड पर हमेशा की तरह प्राचीन शिव मंदिर में भोलेनाथ को पानी में डूबो दिया इसके पूर्व जनपद सदस्य श्रीमती सरोज राठौर एवं जितेंद्र राठौर के मार्ग दर्शन में पंडित उल्लास के कतपूरे ने विधिवत भोलेनाथ की पूजा अर्चना की तत्पश्चात महिलाओं और पुरुषो ने शिव मंदिर में भोलेनाथ के जयकारे हर हर महादेव के जयघोष के साथ शिवलिंग एवं नंदीश्वर को पानी में डुबोया अंत में भोलेनाथ की आरती की गई इस।

बरसात अवश्य होती है- अवसर पर बालमुकुंद राठौर रामराव गलफट सहित अनेक लोग उपस्थित थे खेड़ी के समाजसेवी जितेंद्र राठौर का कहना है जब भी शिव जी की साधना आराधना की है बरसात अवश्य होती है तपस्वी महाराज दामजी बाबा की तपोस्थली है यह ऐसा माना जाता है।

घोड़ाडोंगरी रेलवे गेट, सड़क यातायात चार दिनों तक रहेगा प्रभावित

बैतूल। भोपाल से इटारसी और शाहपुर के रास्ते होकर छिंदवाड़ा की ओर जाने वाले बरेठा-सारणी मार्ग पर स्थित घोड़ाडोंगरी रेलवे गेट 247 चार दिनों तक बंद रहेगा। रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर घोड़ाडोंगरी ने बताया कि यह रेलवे गेट बंद 28 जून 2024 से 1 जुलाई 2024 तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी। रेलवे गेट 247 पर यह बंद रेल पथ अनुरक्षण के कार्यों के लिए की जा रही है। इस दौरान रेलवे ट्रैक की पटरियों पर सुधार और मरम्मत का काम किया जाएगा। रेलवे ट्रैक की पटरियों की मरम्मत से सुरक्षा बढ़ाने और ट्रेन संचालन में सुधार लाने की उम्मीद है। इस महत्वपूर्ण कार्य के दौरान, सड़क यातायात आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा।

यातायात पर असर- घोड़ाडोंगरी रेलवे गेट पर चलने वाला बरेठा-सारणी मार्ग एक महत्वपूर्ण कनेक्शन है जो बैतूल से परासिया को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे से मिलता है। इस मार्ग पर यातायात के बंद से स्थानीय निवासियों और दैनिक यात्रियों को असुविधा हो सकती है। हालांकि, रेलवे प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि इस दौरान

सड़क यातायात को एक लेन से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए समय-समय पर यातायात नियंत्रित किया जाएगा ताकि यात्री बिना अधिक परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुंच सकें।

यात्रियों के लिए सुझाव- इस मार्ग का उपयोग करने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना को इन रातों के दौरान समायोजित करें। अगर संभव हो, तो वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। विशेषकर भारी वाहनों के चालकों को इन दिनों में इस क्षेत्र से बचने की सलाह दी जाती है ताकि यातायात जाम और अन्य समस्याओं से बचा जा सके।

स्थानीय निवासियों का सहयोग- स्थानीय निवासियों से अनुरोध है कि वे रेलवे के इस महत्वपूर्ण सुधार कार्य में सहयोग करें। रेलवे गेट बंद होने की जानकारी को ध्यान में रखते हुए अपनी दिनचर्या में बदलाव करें और संभव हो तो इन रातों के दौरान यात्रा से बचें। रेलवे प्रबंधन का यह कदम यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, और इसे सफल बनाने में सभी का सहयोग आवश्यक है।

घोड़ाडोंगरी रेलवे गेट पर होने वाले इस चार दिवसीय मरम्मत कार्य से यातायात कुछ हद तक प्रभावित होगा, लेकिन यह सुधार यात्रियों की दीर्घकालिक सुरक्षा और यात्रा की सहजता के लिए महत्वपूर्ण है। घोडाडोंगरी रेलवे प्रबंधन ने यात्रियों और स्थानीय निवासियों से अनुरोध किया है कि वे इस अवधि के दौरान संयम बनाए रखें और रेलवे प्रशासन का सहयोग करें।

सतरंगी माह : कितना बदला समलैंगिक समाज?

सामयिक

विवेक रंजन सिंह

लेखक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में पत्रकारिता विभाग के छात्र हैं।

पूरा जून का महीना समलैंगिक समाज के गर्व करने का महीना है। इस महीने में पूरी दुनिया के समलैंगिक समाज के लोग प्राइड मार्च निकालकर समाज में अपने अस्तित्व का संदेश देते हैं। वो बताने की कोशिश करते हैं कि उनका व्यवहार अप्राकृतिक नहीं है बल्कि वो भी अन्य लोगों की तरह सामान्य है।

पिछले एक दशक में भारत में भी एल जी बी टी क्यू समाज को लेकर थोड़ा बहुत नजरिया सामान्य हुआ है। इस समाज की स्वीकार्यता समाज में बढ़ी है मगर इस समुदाय से जुड़े लोगों के लिए यह लड़ाई अभी भी इतनी आसान नहीं है।

आइए जान लेते हैं कि क्यों जून का महीना ही प्राइड मंथ के रूप में मनाया जाता है। इसकी कहानी जुड़ी है अमेरिका के स्टोनवेल में हुए आंदोलन से, जहां 28 जून, 1969 को अमेरिकी पुलिस ने स्टॉनवेल इन नाम के एक रेस्टोरेंट में छापा मारा और पार्टी कर रहे समलैंगिक लोगों पर हमला किया। इसके बाद देखते देखते भीड़ भी विद्रोही हो गई और हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। वहीं से समलैंगिक मुक्ति आंदोलन चला और ये अपने आप में ऐसा पहला आंदोलन माना जाता है। उस दौरान यह आंदोलन कई दिनों तक चला। नतीजतन न्यूयार्क पुलिस और समलैंगिक लोगों के बीच तनाव बढ़ गया। कई संगठन भी इस आंदोलन के पक्ष में सड़कों पर उतर आए। उसी समय कई पत्र पत्रिकाएं भी समलैंगिक आवाजों को बुलंद करने के लिए छापी जाने लगीं। अगले वर्ष, 28 जून, 1970 को शिकागो में गे प्राइड रैलियां आयोजित की गईं, ताकि इस कार्यक्रम की एक साल की सालगिरह मनाई जा सके। कई जगहों और देशों में समलैंगिक संगठनों की स्थापना के बाद हर साल जून के महीने में प्राइड मंथ मनाया जाता है।

भारत में समलैंगिक समाज को हमेशा से हेय नजरिए से देखा जाता रहा है। अधिकार मिलने और धारा 377 में हुए बदलाव के बाद भी अभी नज़रिये में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। इतना सबल जरूर मिला है कि समलैंगिक समाज खुलकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ पा रहे हैं। जब तक धारा 377 के अंतर्गत प्रावधानों में समलैंगिक रिश्ते बनाने को अपराध माना जाता रहा तब तक इस समाज से जुड़े लोगों को रोज समाज में घुट घुट कर जीना पड़ रहा था। न जाने कितने लोगों को पुलिस टॉर्चर और ब्लैकमेल करती रही और मजबूरन उन्हें आत्महत्या भी करनी पड़ी। जस्टिस दीपक मिश्रा की बेच ने जब इस काले कानून में बदलाव कर फैसला सुनाया तो ये बात भी कही कि हमें इतिहास में हुई घटनाओं और उनके (समलैंगिक समाज) साथ हुए अत्याचार के लिए माफी मांगनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के 2018 में आए इस फैसले में जस्टिस मिश्रा और उनकी बेंच की ओर से साफ साफ कहा गया था कि यह किसी भी व्यक्ति के जीवन और उसकी निजता से जुड़ा मामला है। फैसला आने के बाद समलैंगिक समाज में खुशी की लहर जरूर दौड़ी मगर समाज के भीतर कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। नाज फाउंडेशन जैसी संस्थाओं की लड़ाई से यह जीत तो मिली मगर जमीनी और जेहनी तौर पर अब भी भारत में लोग इस समुदाय के प्रति नॉर्मल नहीं है। सरकार भी समाज के भीतर इस समुदाय के प्रति दृष्टिकोण बदलने को लेकर कोई खास प्रयास नहीं की। भारत में दूरदर्शन ने परिवार नियोजन से जुड़े विज्ञापनों को खुलकर चलाया है मगर ट्रांस और समलैंगिक समाज के लिए अभी तक कोई विज्ञापन सरकार की ओर से नहीं चलाया गया। निजी संस्थाओं और फिल्मों ने जरूर इस मुद्दे को उठाना शुरू किया है। पिछले एक दशक में गे,

लेस्बियन और ट्रांस समाज के ऊपर काफी अच्छी फिल्में बनी हैं। जिससे लोगों का नजरिया थोड़ा बहुत सही हुआ है।

पिछले साल आए एक फैसले में कहा गया कि समलैंगिक समुदाय में विवाह को लेकर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। आपको बता दें कि देश के भीतर कई ऐसे मामले आ चुके हैं जिसमे समलैंगिक समाज के कपल एक दूसरे से शादी रचा चुके हैं मगर उन्हें कानूनी मान्यता मिलना अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है।

2009 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस कानून को रद्द किया जिसे बाद में 2013 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः अपराध की श्रेणी में रख दिया। बाद में कुछ संस्थाओं और इस समुदाय से जुड़े लोगों ने याचिकाएं डाली जिसके बाद सुनवाई शुरू की गई और अंततः 2018 में इस काले कानून को खतम कर दिया गया।

शहर में यह समाज अपने मुक्ति और अपने अधिकार की लड़ाई थोड़ी आसानी से लड़ लेता है मगर ग्रामीण क्षेत्रों में इस समाज के खुलकर जीने में अभी भी कठिनाई है। अगर यह समाज खुलकर सामने आ भी जाता है तो उसके प्रति समाज का व्यवहार तुरंत ही बदल जाता है। ऐसे में उन्हें अकेलेपन की जिंदगी जीनी पड़ती है। समाज के भीतर इस समुदाय को दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आज पांच साल हो गई है धारा 377 को हटे हुए मगर ये लड़ाई अभी भी खुद इस समाज की लड़ाई बनी हुई है।

दिल्ली और मुंबई की सड़कों पर सतरंगी झंडा लेकर, अपने खुशी और प्रेम का खुला इजहार करते हुए ये लोग समाज में बस यही संदेश देते हैं कि उन्हें भी अपने बीच का मानें। उनके भी प्रेम और इमोशंस को समझें। धीरे धीरे लोग बदल रहे हैं मगर समस्या अभी भी काफी बनी हुई है जिसको आने वाले समय में संघर्ष के बल पर ही ठीक किया जा सकेगा।

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई सारी फिल्मों ने लोगों की मानसिकता बदली है। शुभ मंगल ज्यादा सावधान,बधाई दो, अलीगढ़,ताली जैसी फिल्मों के माध्यम से इस वर्ग का संघर्ष और उनका नायकत्व काफी प्रभावशाली रहा है। अभिनेताओं ने भी खुलकर इस समाज के लिए आवाज उठाया। साहित्य जगत में भी काफी कुछ इस समुदाय के लिए लिखा जा रहा है। अमित गुप्ता की किताब 'डेहरी पर ठिठकी धूप' में इस विमर्श को काफी गहराई से समझाया गया है। पिछली साल आई कोबाल्ट ब्लू नामक फिल्म ने इस समुदाय के भीतर पल रही एक बड़ी समस्या से अवगत कराया। ज्यादातर समलैंगिक समाज से जुड़े लोगों को उनके ही किसी साथी या पार्टनर द्वारा इमोशनली टॉर्चर किया जाता है।

अब समय है कि मानसिकता बदली जाए। सड़कों पर प्राइड मंथ की रैली में प्रेम का इजहार करते इन लोगों को प्रेम के नजरिए से देखा जाए। इनके प्रति घृणा भावना का त्याग कर इनको गले लगाया जाए। उन्हें औरों की तरह अपना दोस्त बनाया जाए। उन्हें भी अपने आस पास और साथ बेझिझक बिठाया जाए। उनसे बातें की जाएं। कुछ उनकी सुनी जाएं और कुछ अपनी सुनाई जाए। शायद वो भी ऐसा ही सोच रहे होंगे। वो इंतजार कर रहे होंगे कि कब ये समाज उनका सहारा बनेगा। उनके हक और अधिकार की लड़ाई में उनके साथ कदमताल करेगा। समय परिवर्तन का है और इस नए युग के परिवर्तन में हम सबको साझीदार बनना चाहिए।

रसूखदार के संरक्षण में अब 52 साल पुरानी रसायन विज्ञान वाली प्रयोगशाला ले रही नया आकार..

नर्मदापुरम- संजीव डे राय

नगरपालिका के नाम दर्ज भूमि 15/1 पर निर्मित शासकीय नर्मदा महाविद्यालय का यह विंग जो 1982 से पहले महाविद्यालय की रसायन विज्ञान प्रयोगशाला हुआ करती थी वह 52 साल बाद आज नया आकार पा रही है, कितना अजीब है ना..? आश्चर्य होता है 52 साल पहले कक्का जी (स्व रामलाल शर्मा) द्वारा निर्मित करवाई गई निजी नर्मदा महाविद्यालय की यह प्रयोगशाला 52 साल के हवा पानी के थपेड़े खाकर आज भी मुस्कुरा रही है, हवा पानी के थपेड़े 52 साल में उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए लेकिन दूसरी तरफ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा 2003-04 में निर्मित स्कूल भवन मात्र 18 साल में कमजोर साबित हो गया कि उसे खतरनाक घोषित कर तुड़वाना पड़ा.! यह साजिश तो नहीं..? वैसे यहां निर्मित इस सरकारी रसायनिक प्रयोगशाला सहित चार अन्य सरकारी क्वार्टर रसूखदार द्वारा हथियाने की कहानी अब कम लोगों के जेहन में होगी क्योंकि वक्त के साथ बहुत प्रत्यक्षदर्शी अब इस दुनिया में नहीं जो यहां अतिक्रमण कारी रसूखदार की ज्यादती के शिकार हुए थे। नगरपालिका के रकबे पर खड़े सरकारी मकानों को खाली करने के लिए मजबूर थे।

पूजन-हवन के साथ सत्यनारायण भगवान प्रतिमा का पुर्नस्थापना महोत्सव प्रारंभ

आज भगवान की प्रतिमा को करवाएंगे नगर भ्रमण

धार। सकल पंच राठौड़ समाज के उटावद दरवाजा स्थित 100 वर्ष प्राचीन श्री सत्यनारायण भगवान के मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। 28 जून शुक्रवार को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रातः पूजा एवं हवन प्रारंभ हुआ। हवन में समाज के लगभग 21 जोड़े शामिल हुए। तीन दिवसीय महोत्सव के तहत 30 जून को भगवान श्री सत्यनारायण की प्रतिमा को नवीन मंदिर में पुर्नस्थापित किया जाएगा। सकल पंच राठौड़ समाज अध्यक्ष गिरीश राठौड़ एवं मंदिर जीर्णोद्धार समिति अध्यक्ष सन्नी राठौड़ ने बताया कि लंबे समय से मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य राजस्थान के कारिगरों से करवाया जा रहा था। शुक्रवार से शुरू हुए आयोजन में बारिश को दृष्टिगत रखते हुए पूरे मंदिर परिसर में डोम लगाया गया है। जिससे बारिश से किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं उत्पन्न होगा। पूजन विधि आचार्य पंडित गोपाल जोशी एवं उनकी टीम द्वारा करवाई जा रही है। इस दौरान दश विध स्नान, देवता स्थापना, जलाधिवास, गृह होम, सायंतन पूजन व आरती की गई। शाम 7 बजे नवयुवक मंडल अध्यक्ष विजेन्द्र राठौड़ के

नेतृत्व में वाहन रैली भी निकाली गई।

आज करवाएंगे नगर भ्रमण.. – महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार को समाज धर्मशाला से भगवान की प्रतिमा को सुसज्जित बग्घी में विराजित कर नगर भ्रमण कराया जाएगा, जो मोहन टॉकिज हटवाड़ा होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पुनः मंदिर पर समाप्त होगा।

प्रतिमा नगर भ्रमण के दौरान महामंडलेश्वर डॉ नरसिंह दासजी महाराज, पूर्व केन्द्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, विधायक नीना वर्मा सहित अन्य अतिथिगण भी शामिल रहेंगे। भगवान प्रतिमा के नगर भ्रमण के दौरान समाज के पुरूष वर्ग सफेद वस्त्र एवं महिलाएं लाल चुनरी पहनकर शामिल होगी। वहीं सायं 6 बजे महाप्रसादी का आयोजन रखा गया है। कार्यक्रम में पूरे देश सहित प्रदेश के समाज के पदाधिकारियों को बतौर अतिथि आमंत्रित किया गया है। साथ ही धार सहित आसपास के जिलों से भी समाज बंधु बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होंगे। महिला मंडल अध्यक्ष पूनम मुकेश राठौड़ ने समाज की महिलाओं से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर महोत्सव को सफल बनाने की अपील की है। इसके साथ ही मंदिर परिसर में स्थापित देवता पूजन, ब्राह्मण पूजन, देवता उत्थापन, वास्तु निक्षेप, धान्याधिवास, फलाधि, पुष्पाधिवास, गृह होम, उत्थपन, स्नपन की विधि भी होगी।

30 को होगी पूर्णाहति.... – मीडिया प्रभारी धर्मेन्द्र राठौर ने बताया कि नवनिर्मित मंदिर में भगवान की प्रतिमा की पुर्नस्थापना रविवार को की जाएगी। इसके साथ ही हवन की पूर्णाहुति होगी। इसके पूर्व मंदिर पर कलश, ध्वज व शिखर की स्थापना की जाएगी। समाजजन बोली के माध्यम से कलश, शिखर व ध्वज लगाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे।

जल संचय अभियान के लिए वार्डो में हुई कार्यशाला आयोजित

देवास। अमृत संचय अभियान के अन्तर्गत 4 वार्डो मे रूफ वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक तथा रिचार्ज पिट तकनीक लगाये जाने हेतु गुरुवार 27 जून को नगर निगम द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाये जाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार के मार्गदर्शन मे विधायक एवं महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल, सभापति रवि जैन के द्वारा निगम लोक निर्माण समिती अध्यक्ष गणेश पटेल, वार्ड पार्षदों बाली घोसी, महेश फुलेरी, पार्षद प्रतिनिधि बाबु यादव, नितिन आहूजा, के साथ जन जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया। जिसके अन्तर्गत वार्ड क्रमांक वार्ड 33 विश्रामबाग शिव मंदिर गार्डन, वार्ड 38 विजया रोड, वार्ड 39 सरदार पटेल मार्ग विजयवर्गीय धर्मशाला, वार्ड 15 अमोना शासकीय माध्यमिक विद्यालय मे वार्ड वासियों को रूफ वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक तथा रिचार्ज पिट लगाने हेतु प्रेरित किये जाने हेतु कार्यशाला आयोजित की गई। इन अवसरों पर विधायक एवं महापौर प्रतिनिधि श्री अग्रवाल ने

वार्डवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि अमृत संचय अभियान अंतर्गत बारिश के दौरान अपने घर की छत का पानी बोरवेल के माध्यम से जमीन मे उतारने के लिए रूफ वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक लगाने से बोरवेल का जलस्तर बढ़ेगा। श्री अग्रवाल ने यह भी बताया कि रूफ वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक जिस वार्ड मे सबसे अधिक पानी संचय के लिए लगाई जायेगी उस वार्ड मे 25 लाख की राशि विधायक निधि विकास कार्य के लिए दी जावेगी। सभापति ने कहा कि सभी वार्डो के रहवासी जिनके घर पर बोरवेल है उनको रूफ वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक लगाकर तथा जिन रहवासियों के घर पर बोरवेल नही है उन्हें 4 बाय 4 का सॉकपिट तैयार कर बारिश के पानी का संचय करना होगा जिससे हम पानी को बचा सकते है। सभापति ने यह भी बताया कि आने वाले वर्ष 2035 तक जमीन मे पीने के पानी का जल स्तर एकदम कम हो जायेगा। हम पानी संचय की इस मुहिम को अपनाकर छत का पानी जमीन मे उतारकर अपना भविष्य बचा सकते हैं। इन अवसरों पर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की टीम के मोहन वर्मा, साफीया कुरैशी, गंगा सिंह सोलंकी, हिमांशु कुमावत, हिना राठौर, पार्षद बाली घोसी, महेश फुलेरी, पार्षद प्रतिनिधि बाबु यादव, नितीन आहूजा, महेश सोनी आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रमों मे मांगीलाल विजयवर्गीय, शोभा नायक एवं निगम अधिकारी व कर्मचारी सहित बडी संख्या मे वार्डवासी उपस्थित रहे।

राज्य मार्ग नर्मदापुरम-पिपरिया पर हो रहा है एकत्रित पानी, निचाई से ऊंचाई पर नाला निकालने की कोशिश

हीरालाल गोलानी सोहागपुर।

राज्य मार्ग 22 नर्मदापुरम पिपरिया के सरदार वार्ड के नजदीक स्कूल, ईसाई मोहल्ला, नगरपरिषद स्टेडियम की दुकानदारों एवं निवासियों के लिए बरसात सबसे बनके मुंह बाएं खड़ी हुई है। बरसात प्रारंभ होते ही नागरिक परेशानी में पड़ जाते हैं। इस संबंध में आज होटल वाटिका एवं क्षेत्र के करीबन 17 दुकानदारों ने अनुविभागीय अधिकारी,नगर पालिका अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को अलग-अलग ज्ञापन प्रदान किया हैं। उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण विभाग ने सड़कों पर शहरी क्षेत्रों में सड़क तो बना दी ।लेकिन बरसात के पानी की निकासी पर ध्यान ही नहीं दिया गया। जैसे ही बरसात आती है।यह समस्या सरदार वार्ड एवं आसपास के नागरिकों के सबब बन जाती है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में उक्त बरसाती पानी आसपास की निजी भूमि से निकल जाता था। किन्तु लेवलिंग के कारण उक्त पानी राज्य मार्ग पर फैलता रहता है।

उल्टे बांस बरेली को– हालांकि राज्य मार्ग पर पानी निकासी की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की है। लेकिन जब नगरपालिका क्षेत्र में उक्त समस्या हो ।तो अमुमन इसी विभाग पर दबाव नागरिक बनाते हैं। इसी कारण नगर पंचायत परिषद उक्त स्थान से नाला निर्माण कर रही है। लेकिन इस प्रतिनिधि ने नाला स्थल का निरीक्षण किया। यहां यह कहावत चरितार्थ हो रही है कि 'उल्टे बांस बरेली को' जो खुदाई की जा रही है।वह विपरीत दिशा में जा रही। जहां वाटिका ग्रार्डन के आगे विश्राम गृह की तरफ करीबन दो मीटर की ऊंचाई है।ऐसी स्थिति में पानी के बहाव का सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है? यदि सही दिशा में सरल तरीके से नाला निर्माण होता है तो नगर की चर्चित कालोनी के पास से नाला निर्माण होने से कभी भी पानी निकासी की परेशानी नहीं होगी। देखना दिलचस्प होगा कि निकासी उल्टे बांस बरेली को होगी। यह जनता-जनार्दन की परेशानी पर विराम लगेगा।

प्रशांत जायसवाल ने सुबह सवेरे संवाददाता को बताया कि आज हमने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। जिसमें मुख्य मार्ग पर बरसाती पानी एवं ईसाई मोहल्ले के घरो का रहवास का पानी एकत्रित हो रहा है। जिसकी निकासी कही भी नहीं है। इससे दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है । उल्लेखनीय है कि इसी स्थल के पास नगर परिषद की 17 दुकानें स्टेडियम परिसर में है। तथा कई

अन्य दुकानें निर्माणाधीन है। वहीं ईसाई मोहल्ले के निवासियों निकासी भी पानी साल भर रोड़ पर एकत्रित होता है। लेकिन नगर पंचायत परिषद ने पानी निकासी के इन्तजाम नहीं किए हैं। श्री जायसवाल ने आगे कहा कि नगर पंचायत परिषद के लिए निर्माणाधीन सी.एम.राईज स्कूल के पानी के निकासी की व्यवस्था को सुनिश्चित की जा सकती है। वर्तमान में नगर परिषद कच्चा नाला हमारे प्रतिष्ठान होटल वाटिका एवं जायसवाल पेट्रोल पंप के सामने से करीबन 8से 10 फुट की ऊंचाई तक खोदा जा रहा है। जिससे राज्य मार्ग नर्मदापुरम पिपरिया होने से यातायात का दबाव रहता है। जिससे हमेशा दुर्घटनाओं की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। वहीं नाले को दो मीटर की ऊंचाई पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मढ़ई एवं सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल जानेवाले मुख्य मार्ग को ही क्रास करेगा। इससे छात्र छात्राओं के अलावा पर्यटकों के लिए परेशानी के साथ दुर्घटनाओं को आमंत्रण करने वाला रहेगा। आपने आगे कहा कि जहां नाले का लेवल कम है। वहां न करके तीन चार मीटर की ऊंचाई पर विपरीत दिशा में जाने से पानी का बहाव कैसे संभव हो पाएगा। यह विचारणीय प्रश्न है।

सुझाव

सी.एम. राईज स्कूल के पीछे से नगर परिषद के गार्डन के समीप के नाले में इस निकासी पानी को मिलाया जा सकता है। प्रशांत जायसवाल ने नाले लेवल का नक्शा ज्ञापन पत्र के साथ अधिकारियों को संलग्न करके प्रदान किया है। वहीं सुबह सवेरे संवाददाता को बारीकी से गुण दोषों पर नक्शे के साथ ध्यानाकर्षण किया। आपने उच्च अधिकारियों से निरीक्षण करके उचित अत्रुटि पुर्ण कार्यवाही करके नागरिकों को परेशानी से बचाने की मांग की है।

नगर पंचायत परिषद उपमंत्री

इस संबंध में नगर पंचायत परिषद उपमंत्री रामगोपाल चौबे ने बताया कि कैसे तो राज्य मार्ग की जुम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की है। किन्तु नगर की समस्या होने के कारण नगर पंचायत परिषद को सबसे पहले निदान करने को नागरिक कहते हैं।जो नाला निर्माण कराया जा रहा है।इसके लिए करीबन तीस लाख रूपये की राशि आवंटित कराई जा रही है। इसके पुनः अवलोकन होने की संभावना है।

नगर पंचायत ने किया मलासुर अभियान का आयोजन

सुबह सवेरे सोहागपुर ।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत नगर पंचायत परिषद के तत्वावधान में नागरिक सहभागिता से विशेष सफाई अभियानों के अंतर्गत आज मुख्य बाजार में 'मलासुर अभियान' का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत परिषद के कर्मचारियों ने नागरिकों को हर 3 साल में सेप्टिक टैंक खाली कराए जाने की मैनूअल स्केवेजिंग,असुरक्षित स्लजिंग को रोकने के लिए हेल्पलाइन 14420 की बात विस्तार से बताई गई। मलासुर अभियान के तहत नागरिकों से आग्रह किया गया कि अपने सेप्टिक टैंक को अधिकृत डिस्लजिंग ऑपरेटर से ही खाली कराए। क्योंकि हाथ से मैला ढोने की प्रथा पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति होने पर 14420 हेल्पलाइन पर भी संपर्क किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि शहरी स्वच्छता आधारित एक दिवसीय सफाई अभियानों का माह जून एवं जुलाई का शासन द्वारा निर्धारित किया गया है ।जिसमें 25

जून 2024 से 23 जुलाई 2024 तक की गतिविधियों का अलग-अलग दिवस पर आयोजन किया जाएगा। जिसमें सी एंड डी अपशिष्ट संग्रहण अभियान, मलासुर अभियान, बैकलेंस ब्यूटीफिकेशन कैंपेन, किचन टू कंपोस्ट, होम कंपोस्टिं, प्लॉग रन, जीरो वेस्ट कार्यक्रम, मेरी गली सबसे सुंदर अभियान, पर्यटक स्थलों, स्मारकों पार्कों की सफाई अभियान एवं सिंगल यूज प्लास्टिक क्लीनअप ड्राइव अभियान शामिल हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी जीएस राजपूत ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार माह जून एवं जुलाई में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा । आपने नागरिकों से अधिक से अधिक नागरिक सहभागिता निभाने का आग्रह किया है।

राइट क्लिक

लोकतंत्र की कसौटी पर 'संविधान' और 'आपातकाल'

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के वरिष्ठ संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

संविधान बनाम आपातकाल, संविधान को बचाने बनाम संविधान बदलने की छिपी मंशा, नौकरी व शिक्षा में जाति आधारित आरक्षण की रक्षा बनाम जातिगत आरक्षण के खात्मे की नीयत, लोकतंत्र जिंदा रखने बनाम लोकतंत्र के मुखौटे में तानाशाही लागू करने की मंशा...। ये कुछ ऐसे सुलगते मुद्दे हैं, जिन पर अब देश में परसेप्शन की लड़ाई लड़ी जा रही है। एक मायने में यह अच्छा इसलिए है, क्योंकि लोकतंत्र के संदर्भ में एक सैद्धांतिक वाद- विवाद सियासत के केन्द्र में है। हालांकि इसका इस्तेमाल सत्ता को कायम रखने अथवा उसे छीनने के उद्देश्य से किया जा रहा है। तर्कों, कुतर्कों, आशंकाओं और जिद के धुंध में देश के आम आदमी के लिए समझना मुश्किल है कि सच क्या है? इसमें कौन दूध का धुला है, किसके हाथों में संविधान एक पवित्र ग्रंथ की सुरक्षित है और किसके हाथों में संविधान की हत्या का छुपा खंजर है? लेकिन हैरानी की बात यह है कि संविधान की पवित्रता की कायमी की दुहाई के साथ किसी स्तर पर कोई पश्चात्ताप का भाव नहीं है।

इस देश में 2024 के पहले हुए तमाम चुनावों में आरक्षण व अन्य जमीनी मुद्दे तो चर्चा में रहे हैं, लेकिन यह पहला चुनाव था, जिसके केन्द्र में संविधान और उसकी रक्षा का मुद्दा आ गया या लाया गया था। मसलन देश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, संविधान को दबे पांव बदलने, संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बनाने या फिर पिछले दरवाजे से निरंकुश शासन की आहट की आशंकाएं भी हवा में थीं, लेकिन बात सीधे संविधान पर आ टिकेगी, ऐसा चुनाव के शुरू के दो चरणों में भी नहीं लगा था। शुरू में कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों को भी इस मुद्दे की राजनीतिक ताकत का अहसास नहीं था और वे मोटे तौर महंगाई, बेरोजगारी, जाति जणना, मोदी की निरंकुशता जैसे मुद्दों पर ही चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चुनाव की पूर्व बेला में पीएम मोदी के एक अवास्तविक दावे 'अबकी बार चार सौ पार' को टेका लगाने जब कुछ भाजपा नेताओं ने यह कहना शुरू किया कि 'चार सौ पार' संविधान में बदलाव के लिए चाहिए तो किसी निर्णायक मुद्दे की तलाश में भटक रहे विपक्ष को मानो जादू का चिराग मिल गया। तत्काल संविधान की प्रतियां हाथ में ले लेकर उसे बचाने की सार्वजनिक कसमे खाई जाने लगी। कहा गया कि मोदी और भाजपा की असल मंशा उस संविधान को बदलने की है, जिसने ओबीसी, दलित और आदिवासियों को बराबरी के अधिकार और आरक्षण दिया है। अगर भाजपा के पास बहुत ज्यादा ताकत आ गई तो संविधान में संशोधन कर वो यह सब खत्म कर देगी। हालांकि स्पष्ट तौर किसी ने भी नहीं कहा था कि संविधान को बदलने से ठीक-ठीक क्या आशय है? क्या जातिगत आरक्षण को खत्म करना, संविधान की उद्देशिका में 26 साल बाद संविधान संशोधन के जरिए जोड़े गए 'समाजवादी' और 'पंथ निरपेक्ष' राष्ट्र शब्दों को हटाना अथवा भारत को आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करना। दरअसल संविधान में बदलाव की जो सुरसुरी खुद भाजपाइयों ने शुरू की थी, उसका भाजपा ने कभी भी सुस्पष्ट तौर पर खंडन नहीं किया। वह अपनी 'यह भी सही और वह भी सही' की पुरानी रणनीति पर कायम रही। संविधान को सिर माथे रखकर उसने सफाई दी भी तो बहुत देर से। नतीजा उसे 2019 की तुलना में 63 सीटों के भारी नुकसान के रूप में हुआ। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने जो नरेटिव बनाया कि भाजपा कुछ भी कहे, संविधान को लेकर उसके इरादे नेक नहीं है, वह गरीबों को मिले अधिकार छीनना चाहती है। धारणा का यह ब्रह्मास्त्र कुछ राज्यों में काम कर गया।

ऐसे में केन्द्र में तीसरी बार एनडीए सरकार बनाने के बाद मोदी और भाजपा ने विपक्ष के 'संविधान कार्ड' की काट इमर्जेंसी में ढूंढने की कोशिश की है। असल में यह राजनीतिक पलटवार है, जिसमें संदेश निहित है कि जो कांग्रेस और राहुल गांधी संविधान की प्रति रामचरित मानस के गुटके की तरह हाथ में लिए उसकी पवित्रता कायम रखने की कसमें खा रहे हैं, खुद उनकी दादी और कांग्रेस पार्टी संविधान को बदलने का 'पाप' 1976 में 42 में संविधान संशोधन के जरिए कर चुकी है। ऐसे मे भाजपा को कटघरे में खड़ा करना 'उलटा चोर कोतवाल को डांटे' वाली अदा है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि यह संशोधन उस वक्त किया गया, जब देश में आपातकाल लगा था। लोगों के मौलिक अधिकार निलंबित थे। लाखों इंदिरा विरोधी व विपक्षी जेल में डाल दिए गए थे। लोकसभा में इस बिल का विरोध केवल उन पांच सांसदों ने किया था, जो कांग्रेस में 'असंतुष्ट' माने जाते थे। जबकि 21 विपक्षी सांसद मीसा एक्ट में जेल में बंद थे। राज्य सभा में किसी ने भी इस बिल का विरोध नहीं किया। इस संविधान संशोधन के जरिए संविधान की उद्देशिका में तीन बातें जोड़ी गईं। यह है भारत का 'समाजवादी, पंथ निरपेक्ष' (सेक्युलर) होना तथा देश राष्ट्रीय एकता और अखंडता कायम रखना। तीसरे मुद्दे पर कहीं कोई विवाद नहीं था। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा संविधान की उद्देशिका में 'समाजवादी और पंथ निरपेक्ष' जोड़े जाने पर सवाल उठे। क्योंकि संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर लिखित और तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू की असंदिग्ध सेक्युलर प्रतिबद्धता के बाद भी उद्देशिका में इन दो शब्दों को अलग से जोड़ने की जरू रत नहीं समझी गई। माना गया कि जब संविधान की उद्देशिका में भारत के सभी नागरिकों को 'सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय' की गारंटी दी गई है तो इसमें समाजवादी व्यवस्था का भाव स्वतः निहित है। इसी तरह जब हर नागरिक को विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है तो इसे अलग से 'पंथ निरपेक्ष' के रूप में मुहर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी ये दो शब्द जोड़े गए तो इसके पीछे कौन सा तात्विक आग्रह, भविष्य का भय या राजनीतिक दांव था, यह बड़ा सवाल है। क्या किसी ने ऐसी मांग की थी, क्या यह केवल वाम पंथियों का समर्थन हासिल करने और उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर करने की चाल थी? क्योंकि उस वक्त भी हिंदू राष्ट्र की बात करने वाली तत्कालीन जनसंघ (अब भाजपा) की राजनीतिक शक्ति बहुत कम थी। 1971 की प्रचंड इंदिरा लहर में जनसंघ के मात्र 22 सांसद चुनकर आए थे और आरएसएस प्रेरित जनसंघ का वोट प्रतिशत भी मात्र 7.3 था। जो इसके पूर्ववर्ती 1967 के लोस चुनावों की तुलना में और घट गया था। आपातकाल में और भी कई ज्यादतियां हुईं। इसका नतीजा 1977 के आम चुनाव में इंदिराजी को भुगतना पड़ा। वे खुद हारीं और कांग्रेस भी सत्ता से बाहर हो गई। 1980 के चुनाव के पहले इंदिराजी को अपनी गलती का अहसास हुआ। लेकिन तब तक देश की राजनीति का रंग बदलने लगा था। इंदिराजी दोबारा पूरी ताकत से सत्ता में लौटीं और आपातकाल की कहानियां धीरे- धीरे हाशिए पर जाने लगीं। यहां तक कि 1999 में जब देश में अटलजी के नेतृत्व में एनडीए सरकार थी, तब भी आपातकाल की 25 वीं बरसी को वैसी तवज्जो नहीं मिली, जिस तरीके से मोदी सरकार ने अब 50 वीं बरसी पर इसे हवा दी है। नए लोस स्पीकर ने कुर्सी संभालते ही आपातकाल के दौरान राजनीतिक प्रताड़ना के कारण जान गंवाने वालों को सदन में श्रद्धांजलि दी। जिसका कांग्रेस को छोड़कर सभी ने समर्थन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में आपातकाल के काले दिनो का जिक्र किया। मप्र सरकार ने आपातकाल को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का ऐलान किया। मध्यप्रदेश में मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी मानकर उन्हें 30 हजार रू. प्रतिमाह की पेंशन भी दी जाती है। मीसाबंदियो को लोकतंत्र सेनानियों की संज्ञा दी गई। क्योंकि उन्होंने स्वदेशी सत्ता और निरंकुशता के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।

निश्चय ही कांग्रेस उन 'काले दिनो' को याद नहीं करना चाहती, जबकि भाजपा की चाल यही है कि संविधान बचाने की बात करने वाली कांग्रेस को आपातकाल का आईना बार बार दिखाकर वो मूल संविधान याद दिलाया जाए जो 1976 के संशोधन के पहले का है। यानी भाजपा अतीत का रियर ग्लास दिखाकर सत्ता की गाड़ी आगे हांकना चाहती है तो कांग्रेस नीयत के दर्पण में भाजपा को आईना दिखाकर राजनीतिक बाधा दौड़ जीतना चाहती है तो कांग्रेस का प्रयास उस भय को मेग्नीफाई करने का है कि जिस दिन भाजपा के पास निरंकुश सत्ता होगी, वह संविधान को 'मनुस्मृति' में तब्दील करने में देर नहीं करेगी। इसलिए यह बार बार कहा जा रहा है कि देश में दस साल से अघोषित आपातकाल है, जो घोषित आपातकाल से भी बदतर है। जबकि सत्य इन दोनों के बीच कहीं है।

इमर्जेंसी पर रक्षात्मक दिखने वाली कांग्रेस 'संविधान बचाने' की रणनीति पर अभी और आगे बढ़ सकती है। क्योंकि इसी साल तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 'संविधान बचाओ' का नारा इनमे कितना चलेगा, यह देखने की बात है। अमूमन चुनावी 'काठ की हांडी' की तरह एक बार ही चढ़ते हैं। जो मुद्दा एक चुनाव में चल गया, वो दूसरे में भी चले, यह जरूरी नहीं है। फिर इतिहास के गड़े मुर्दे हर बार सियासी दलों के अनुकूल बोली ही बोलें, यह भी कम ही होता है। जनता का रोष एक बार निकलने के बाद उसी मुद्दे पर उसमें दोबारा जोश भरना आसान नहीं है। फिर भी चुनावी हानि लाभ से हटकर अच्छी बात यह है कि कुछ बुनियादी मसलों और प्रतिबद्धताओं पर तीखी बहस हो रही है, इस पर कौन कितना खरा उतरता है, यह जल्द ही पता चल जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2023 बैच के 9 परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने भेंट की

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से आज मंत्रालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2023 बैच के 9 परीक्षा परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने भेंट की। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव श्री संजय कुमार शुक्ला, श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, प्रशासन अकादमी के महानिदेशक श्री विनोद कुमार और संचालक, प्रशासन अकादमी भोपाल श्रीमती सोनाली वायंगणकर उपस्थित थीं।

कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षाओं के परिणाम घोषित

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ली गई कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड पेटर्न पुनः परीक्षाओं का परिणाम शुक्रवार को राज्य शिक्षा केन्द्र के परीक्षा पोर्टल पर घोषित कर दिये गये हैं। संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र श्री हरजिंदर सिंह ने बताया कि विद्यार्थी, अभिभावक एवं शिक्षकगण इन परिणामों को राज्य शिक्षा केन्द्र के वेबपोर्टल पर अपना रोल नम्बर प्रविष्ट कर देख सकते हैं। इसी पोर्टल पर शिक्षक, संस्था प्रमुख को भी अपनी शाला का विद्यार्थीवार परिणाम देखने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इन परीक्षाओं का संचालन गत 3 से 8 जून के दौरान किया गया था। जिनमें प्रदेश की शासकीय, अशासकीय शालाओं एवं पंजीकृत मदरसों के कक्षा 5वीं के 1 लाख 31 हज़ार से अधिक तथा कक्षा 8वीं के 1 लाख 63 हज़ार से अधिक विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। इन विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए कुल 322 केन्द्र बनाये गये थे, जहां से 28 हज़ार से अधिक मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि पोर्टल पर दर्ज की गई थी।

घोषित परीक्षा परिणामों के अनुसार पुनः परीक्षा में कक्षा 5वीं के 81.71 प्रतिशत विद्यार्थी तथा कक्षा 8वीं के 76.95 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। गत अप्रैल में घोषित मुख्य परीक्षा के परिणाम के बाद कक्षा 5वीं के कुल 1 लाख 81 हज़ार 996 विद्यार्थियों तथा कक्षा 8वीं के कुल 2 लाख 36 हज़ार 475 अनुतीर्ण एवं अनुपस्थित विद्यार्थियों को पुनः परीक्षा की पात्रता प्राप्त हुई थी।

निगम कमिश्नर के चैंबर के बाहर भाजपा पार्षद का धरना

भोपाल के आईएसबीटी ऑफिस में ठेकेदार के साथ बैठे, बोले-4.78 करोड़ नहीं दे रहा निगम

भोपाल (नप्र)। भोपाल के वार्ड-62 से भाजपा पार्षद और जोन-15 के अध्यक्ष राजेश चौकसे ने शुक्रवार को निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। आदमपुर छावनी स्थित कचरा प्रोसेसिंग का काम करने वाले ठेकेदार को 4.78 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं होने से वे नाराज थे। निगम कमिश्नर के चैंबर के सामने जमीन पर ही वे धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि उन्होंने भी मशीनें लगाई हैं। 6 महीने का उन्हें 42 लाख रुपए लेना है, लेकिन कमिश्नर भुगतान नहीं कर रहे हैं।

ठेकेदारों के साथ पार्षद चौकसे भी करीब आधे घंटे तक धरने पर बैठे रहे। उन्होंने बताया, 31 मई को ठेकेदार का टेंडर खत्म हो गया था। इस दौरान लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी थी। इस पर अफसरों ने मौखिक ही कहा कि काम जारी रखें। इसके चलते कचरे की प्रोसेसिंग करने वाली कंपनी के ठेकेदार के 4 करोड़ 78 लाख रुपए बकाया हो गए। कई दिन से बकाया राशि लेने के लिए ठेकेदार निवेदन करते रहे। तीन-चार दिन प्रोसेसिंग बंद रखने के बाद निगम ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए का

भुगतान किया। इसमें भी 62 लाख रुपए जीएसटी के रूप में काट लिए। ठेका कंपनी के अधीन ही हम भी काम करते हैं। मेरे भी 42 लाख रुपए बकाया है, जो नहीं मिले हैं।

कई दिन से गुहार लगा रहा- पार्षद चौकसे ने कहा कि बकाया राशि के भुगतान के लिए मैं भी ठेकेदारों के साथ निगम कमिश्नर नारायण से गुहार लगा रहा हूं, लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा। इसलिए शुक्रवार को कमिश्नर ऑफिस के सामने ही जमीन पर धरने पर बैठे।

महापौर ऑफिस में नोंकझोंक- पार्षद चौकसे ने बताया कि निगम कमिश्नर रूम के बाहर धरना देने के बाद महापौर मालती राय से भी राशि का भुगतान करने का निवेदन किया गया है। आज दोपहर में महापौर ऑफिस में कमिश्नर से मुलाकात हुई। उनसे भुगतान करने को कहा है। इस दौरान नोंकझोंक भी हुई है।

घर-परिवार चलाने के लिए जरूरी है

पार्षद चौकसे ने बताया, समाजसेवा के लिए पार्षद बना हूं, लेकिन घर-परिवार चलाने के लिए व्यवसाय भी जरूरी है। मैं भी व्यवसायी हूं और ठेकेदार को दो पोकलेन, एक जेसीबी दी है। छह-सात महीने का 42 लाख रुपए बकाया है। मेरे कई कर्मचारी हैं। मशीनें चलाने के लिए डीजल का उपयोग भी कर रहा हूं। इसलिए मुझे भी राशि की जरूरत है, लेकिन कमिश्नर भुगतान नहीं कर रहे हैं, जो कि गलत है।

भुगतान नहीं तो काम नहीं करने देंगे

पार्षद समेत ठेकेदारों ने चेतावनी दी कि बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर आदमपुर कचरा खंती में काम नहीं करने देंगे। चाहे निगम कानूनी कार्रवाई ही क्यों न कर दें। निगम परिषद की मीटिंग में भी यह मुद्दा उठाएंगे।

काम बंद होने से कचरे का ढेर लगा

कचरा प्रोसेसिंग बंद होने से आदमपुर छावनी में कचरे का ढेर लग रहा है। शहर से हर रोज करीब 850 टन कचरा यहां पहुंचता है। इसके बाद इसकी प्रोसेसिंग होती है। बता दें कि सर्वेक्षण टीम जुलाई के पहले सप्ताह तक आ सकती है। ऐसे में सर्वेक्षण में दिक्कतें आ सकती हैं।

उद्यानिकी और खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में निवेश का प्रदेश में बेहतर माहौल : मंत्री श्री कुशवाह

देश में उद्यानिकी से फसल उत्पादन में प्रदेश की 11 प्रतिशत भागीदारी

भोपाल (नप्र)। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेशकों के लिए मध्यप्रदेश के द्वार सदैव खुले हैं। प्रदेश में निवेश के बेहतर माहौल और भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उद्यमी उठा सकते हैं। यह बात उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने भोपाल में आयोजित खाद्य प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय शिखर सम्मेलन के शुभारंभ अवसर पर कही। मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि मध्यप्रदेश में 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 400 लाख मीट्रिक टन उद्यानिकी फसलों का उत्पादन होता है। देश में मध्यप्रदेश उद्यानिकी उत्पादन में 11 प्रतिशत, कृषि

उत्पादन में 10 प्रतिशत तथा दुग्ध उत्पादन में 9 प्रतिशत उल्लेखनीय भागीदारी दर्ज करता है। मध्यप्रदेश देश में टमाटर उत्पादन में प्रथम तथा मिर्च, प्याज के उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि विश्व बाजार में प्राकृतिक एवं जैविक उत्पादों की अत्यधिक मांग है। देश में कुल जैविक उत्पादन में मध्यप्रदेश की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इससे स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भागीदारी रखता है। मंत्री श्री कुशवाह ने सम्मेलन में भाग ले रहे व्यवसायियों से अपील की कि वह प्रदेश में उद्यानिकी फसलों पर आधारित व्यवसायिक गतिविधियों में निवेश करें। राज्य सरकार उनकी भरपूर मदद करेगी।

मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि मध्यप्रदेश में विगत वर्षों में खाद्य प्र-संस्करण के क्षेत्र में छोटी-बड़ी 2400 इकाईयों को राज्य सरकार द्वारा 214 करोड़ की अनुदान सहायता दी गई है।

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने मैहर जिले के ग्राम अमदरा में लगाई रात्रि चौपाल

भोपाल (नप्र)। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने गुरुवार को मैहर जिले के भ्रमण के दौरान ग्राम अमदरा में जन चौपाल लगाकर लोगों की बिजली संबंधी समस्याएं सुनी। इस मौके पर अमदरा, नौगवां, खेरवासानी के ग्रामीणों ने ऊर्जा मंत्री को बताया कि बिजली की आपूर्ति संबंधी कोई समस्या नहीं है। सभी क्षेत्रों में बराबर बिजली मिल रही है। किसानों ने सिंचाई के लिए दी जाने वाली 10 घंटे की बिजली लगातार और दिन के समय में देने की मांग की।

ऊर्जा मंत्री ने किसानों से अपने सिंचाई पंपों के लिए सोलर ऊर्जा पंप लगाने की सलाह दी। उन्होंने कहा सोलर ऊर्जा से पर्याप्त बिजली मिल सकेगी। इस अवसर पर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी भी उपस्थित थे।

ऊर्जा मंत्री ने किया राजेश सिंह गोंड के घर रात्रि विश्राम- ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने अमदरा में जन चौपाल के बाद ग्राम अमदरा के सरपंच राजेश सिंह गोंड के तालाब टोला स्थित घर में रात्रि विश्राम किया। उन्होंने विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी के साथ सरपंच के घर में भोजन भी किया।

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने मैहर जिले के ग्राम अमदरा में राजेश सिंह गौड़ के घर में रात्रि विश्राम करने के बाद शुक्रवार की सुबह ग्राम पंचायत अमदरा का भ्रमण किया। उन्होंने इस दौरान बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर और लाइन संधारण कार्य का निरीक्षण किया। अमदरा में 12 ट्रांसफार्मर लगे हैं और 598 बिजली उपभोक्ता है। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने जन चौपाल में ग्रामीण जनों की मांग पर अमदारा में एक नए ट्रांसफार्मर का भूमि-पूजन किया। उन्होंने भ्रमण के दौरान अमदरा के एक बिजली उपभोक्ता के घर बैठ कर चाय भी पी।

50 जनचौपाल में होंगे शामिल- ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपभोक्ताओं से फीडबैक लेने और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए वह 50 जनचौपाल में शामिल होंगे। श्री तोमर ने मैहर में ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि बिजली का निर्बाध आपूर्ति ही शासन का लक्ष्य है। इसे हर हाल में पूरा करें।

भोपाल की मनीषा आनंद ने जीता मिसेज इंडिया खिताब

कहा- सबसे बड़ी चुनौती ग्लैमरस बनना थी, खूब मेहनत की और यह खिताब हासिल किया

भोपाल (नप्र)। भोपाल की मनीषा आनंद ने मिसेज इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन 2024 सीजन-5 का खिताब जीता है। यह प्रतियोगिता पुणे में आयोजित हुई थी। जिसमें 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

मनीषा ने पहले 2023 में मिसेज सेंट्रल इंडिया का खिताब भी जीता था। यह दूसरा मौका है जब भोपाल की किसी महिला ने यह खिताब जीता है। इससे पहले 2023 में अपेक्षा डबराल ने यह खिताब जीता था।

शुक्रवार को मनीषा आनंद ने भोपाल की आदित्य रेजीडेंसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा- मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ग्लैमरस बनना थी। ज्यूरी ने भी उन्हें फीडबैक में यही कहा था। मैंने खूब मेहनत की और अंत में मिसेज ग्लैमरस का खिताब भी हासिल किया। यह सफर भोपाल की कई महिलाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक है।

मनीषा आनंद का कहना है कि सफर में आखिरी लक्ष्य से ज्यादा महत्व हर सेकेंड बेस्ट करने में देना चाहिए, और खुद को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। शुक्रवार को मनीषा आनंद ने मिसेज इंडिया 2024 का खिताब जीतने के बाद प्रेस की।

20 साल से हैं करियर काउंसलर- मनीषा पिछले 20 वर्षों से एक करियर काउंसलर रही हैं। 2023 में अपेक्षा डबराल से मुलाकात के बाद उनका मॉडलिंग करियर शुरू हुआ, जिसके बाद अपेक्षा ने ही उन्हें मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया था।

मनीषा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों के साथ मिसेज सेंट्रल इंडिया की मैनेजर फरहा अनवर को

दिया और कहा कि इस सफर में कई महिलाओं ने उनका साथ दिया है और वो उनसे बहुत इन्स्पायर होती हैं।

मनीषा 20 साल से योग कर रही हैं और खुद को फिट रखती हैं। उन्होंने बताया की जनवरी में मिसेज इंडिया 2024 की तैयारी शुरू की थी और इस प्रतियोगिता के लिए उन्होंने कई नई स्किल डेवलप कर खुद को ट्रांसफॉर्म भी किया है।

मनीषा आनंद की फिल्मी पैरेंटिंग टिप- मनीषा आनंद एक पेजेंट विनर के साथ-साथ एक मां भी है। उनके 2 बच्चे हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि फाइनल राउंड में उनसे उनकी पैरेंटिंग टिप पूछी गई, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने अपनी बेटी के लिए कहा, जा ताशा जा, जी ले अपनी जिंदगी, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।

बता दें, मनीषा आनंद ने गोल्ड कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। गोल्ड कैटेगरी में 35-50 वर्ष की महिलाओं ने भाग लिया था। इसमें एनआरआई के साथ देश भर से 55 महिलाएं शामिल थीं। मनीषा आनंद ने 2024 में इम्प्रेस ऑफ थे नेशन का खिताब जीता।

हमेशा कुछ नया करते रहना चाहिए- मनीषा मानती हैं कि शारीरिक सुंदरता से ज्यादा आपका सही माइंडसेट जरूरी है। कोई भी सफलता कम्फर्ट जोन छोड़ने के बाद ही मिलती है। उनका कहना है कि लोगों को हमेशा कुछ नया करते रहना चाहिए, और हर काम में अपना 100 प्रतिशत देना चाहिए। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव थिंकिंग ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद कि है। अब वो कुछ समय आराम करना चाहती हैं, और आगे जाकर मिसेज यूनिवर्स में भी हिस्सा लेना चाहती हैं।